रायपुर, वर्ष-18, अंक-02, फरवरी 2022, मूल्य ₹ 10

दीप कमल

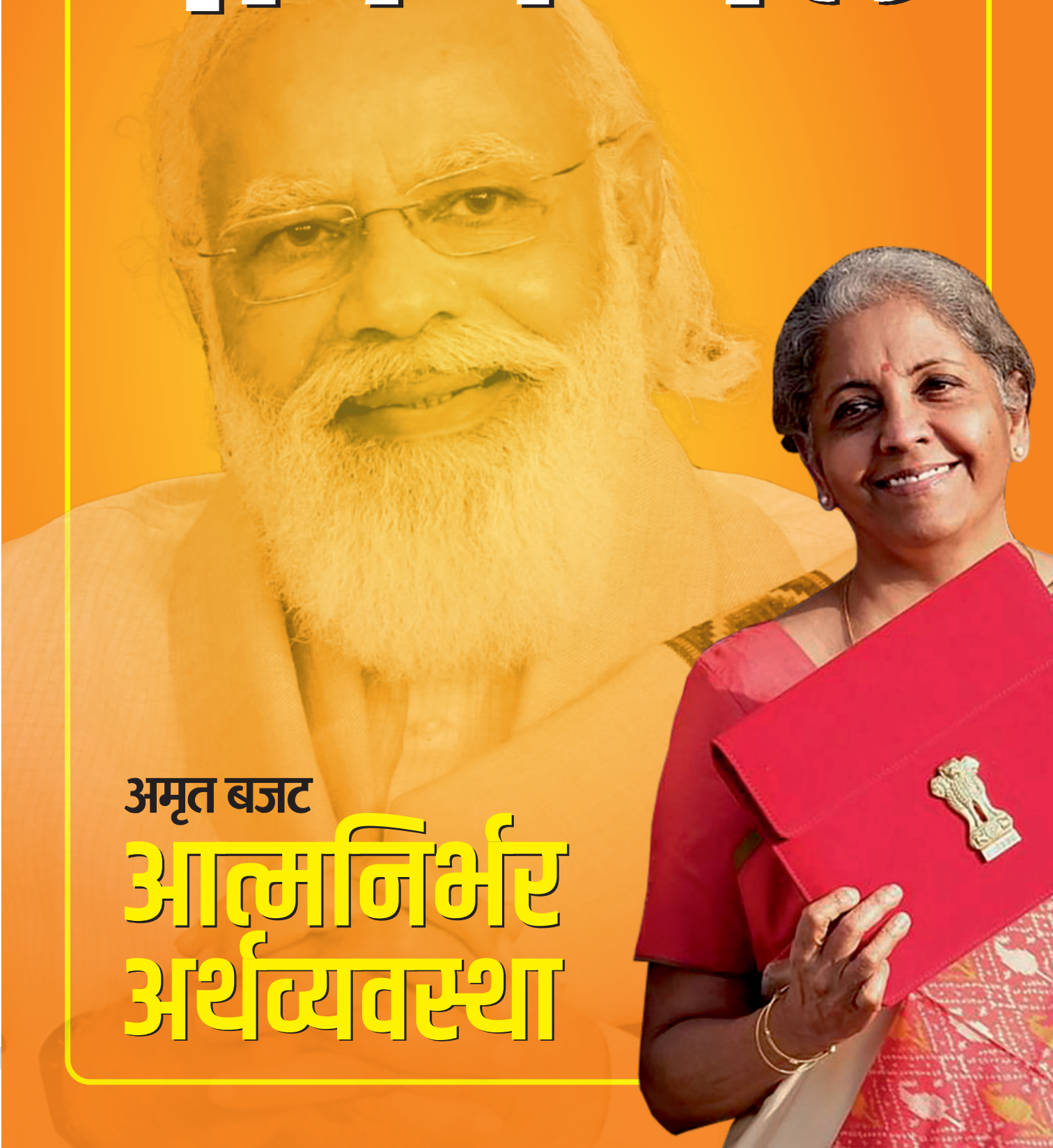

अमृत बजट
आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था

केंद्रीय बजट 2022 विषय पर देशभर के भाजपा कार्यकर्ताओं को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने संबोधित किया।

बजट पर प्रधानमंत्री जी के संबोधन में उपस्थित छत्तीसगढ़ भाजपा के नेतागण।

दीपकमल लोकार्पण समारोह का शुभारंभ।

दीपकमल के अटल स्मृति अंक के लोकार्पण समारोह और गोष्ठी में उपस्थित भाजपाजन।

दीप कमल

संपादक
सुभाष राव

कार्यकारी संपादक
पंकज कुमार झा

मुद्रक एवं प्रकाशक विष्णुदेव साय द्वारा, भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़, के लिए मूणत ऑफसेट प्रिंटर्स रायपुर से मुद्रित एवं एकात्म परिसर, रजबंधा मैदान रायपुर से प्रकाशित।

स्वत्वाधिकारी
भारतीय जनता पार्टी, छत्तीसगढ़

ई-मेल
jay7feb@gmail.com

फोन
0771-2233500, 4266000

सोशल मीडिया से

Tweets | Tweets & replies | Media | Likes

Vishnu Deo Sai @vishnudsai · 12s
स्वर सम्राज्ञी, भारत रत्न हम सबके हृदय में निवास करने वाली दीदी लता मंगेशकर जी के निधन की खबर सुनकर अत्यंत दुखी हूँ। उनके निधन से देश की कला और संस्कृति के क्षेत्र में जो रिक्तता आई है उसे कोई भर नहीं पायेगा।

1 | 3

Vishnu Deo Sai @vishnudsai · 12s
ईश्वर लता दीदी को अपने श्रीचरणों मे स्थान दें, तथा उनके परिजनों और प्रशसंकों को इस वज्रपात को सहन करने की शक्ति । ॐ शांति ।

Tweets | Tweets & replies | Media | Likes

BJP Chhattisgarh @BJ... · 4h
कोरोना के इलाज के नाम पर रायपुर के इंडोर स्टेडियम में बनाए गए अस्थाई कोविड सेंटर में भूपेश सरकार ने किराए के समान के नाम पर ऐसी लूट मचाई कि देखते ही देखते 80 लाख का किराया भर कर सिद्ध कर दिया कि भूपेश राज में छूट है, लूट सके तो लूट..।

शर्म आती है ऐसी सरकार पर।

@bhupeshbaghel

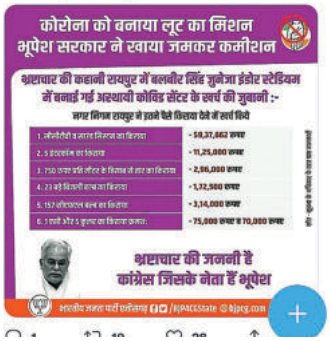

Dr Raman Singh @drraman... · 4m
छत्तीसगढ़ सरकार दिवालिया हो गई है?

शायद ही किसी राज्य में ऐसा होता हो कि निगम मंडलों में इमरजेंसी के लिए जमा राशि को सरकार के के- डिपॉजिट में जमा करने कहा जाए।

3 साल में 51000 करोड़ से अधिक का कर्ज, फिर भी ये स्थिति।@bhupeshbaghel जी ने छत्तीसगढ़ को कांग्रेस का ATM बना दिया है।

Jyotiraditya M... · 05/02/22
छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री एवं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष @drramansingh जी से आज उनके निवास पर सौजन्य भेंट की। इस दौरान छत्तीसगढ़ में हवाई सेवाओं के विस्तार के संबंध में विस्तृत चर्चा भी हुई।

अंदर के पन्नों में

प्रेरक और प्रासंगिक दीनदयाल 06
स्मृति शेष, दाऊ आनंद कुमार 07
हिजाब या अलगाववादी षड़यंत्र 08
आरक्षण विरोधी एजेंडा चला रही है कांग्रेस 09
हम भारत के लोग... 10
राहुल गांधी की गुप्त यात्रा और कांग्रेस ... 14
अर्थव्यवस्था को बूस्टर डोज लगाएगा... 16
पूर्व मंत्री मूणत से थाने में मारपीट... 20
अटल, अडिग, अद्वितीय, अद्भुत और सदा 28
राष्ट्रपति के आदिवासी दत्तक पुत्रों ... 30

अव्यवस्थाओं, विश्वासघातों और झूठ की खेती

छत्तीसगढ़ की ख्याति समूचे देश और दुनिया में भी 'धान के कटोरे' के रूप में यूं ही नहीं है। यहां की शस्य-श्यामला धरती देश के लिए दस करोड़ क्विंटल से भी अधिक धान उगाती है। यूं तो प्रदेश की पहचान इसके वन्य और खनिज संपदा से लेकर यहां के भले और भोले, अच्छे लोगों से भी है लेकिन, कृषि के मामले में भी यह छोटा कहा जाने वाला प्रदेश देश के बड़े प्रदेशों से प्रतिस्पर्द्धा करने को तैयार है। हालांकि अविभाजित मध्य प्रदेश के ज़माने से लेकर छत्तीसगढ़ के निर्माण के शुरुआती कुछ वर्षों तक यहां के हालात अच्छे नहीं थे। वास्तव में इस राज्य के निर्माण की ज़रूरत ही इसीलिए हुई थी क्योंकि यहां के संसाधनों का कांग्रेस के ज़माने में बंदरबांट कर लिया जाता था। यहां के किसान जहां फटेहाली में रहने को विवश थे, तो आदिवासी समाज मामूली चिकित्सा व्यवस्था को भी मुहताज था।

भाजपा की सरकार के सत्ता में आने के बाद पंद्रह वर्ष प्रदेश में अनेक सुधारों के रहे। कृषि के क्षेत्र में हालात यह थे कि पहले जहां खुद कांग्रेस की सरकारें यहां की उपज धान को पानी में डूबा-डूबा कर देखती थी, वही भुगतान के लिए किसानों को लंबा इंतज़ार करना पड़ता था। फिर भाजपा के शासनकाल में काल में धान खरीदी को तकनीकों से जोड़ा गया, मुफ्त कृषि ऋण, खाद-बीज-बिजली की सहज उपलब्धता और बेहतर धान खरीदी के मॉडल ने प्रदेश को कृषि के मामले में भी अवसरों की भूमि बना देने में सफलता पायी। जल्द ही इसके धान खरीदी के मॉडल को जिसमें बिना किसी लीकेज के किसानों के खातों में चौबीस घंटे के भीतर रकम पहुंच जाते थे, की संयुक्त राष्ट्र तक में तारीफ़ होने लगी थी। मोटे तौर पर व्यवस्था ऐसी बन गयी थी कि किसानों को रोपनी के समय ही धान की कीमत अग्रिम मिल जाया करती थी। इसीलिए पड़ोसी प्रदेशों की कुख्याति जहां किसानों के आत्महत्या के मामले में थी, वहां छग में ऐसी खबरें लगभग नहीं आती थी।

लेकिन पिछले तीन साल से जबसे कांग्रेस सत्ता में आयी है, दुर्गति का सिलसिला फिर से शुरू हो गया है। शासकीय आंकड़ों के अनुसार ही पिछले क़रीब दो सालों में (साल 2020 में एक जनवरी से 23 नवंबर तक) छत्तीसगढ़ में 230 किसानों ने आत्महत्या की है। राज्य सरकार के मुताबिक़ ही आत्महत्या करने वाले किसानों में सर्वाधिक 97 आदिवासी समुदाय से हैं। 42 किसान अनुसूचित जाति के हैं। एनसीआरबी की रिपोर्ट बताती है कि 2020 में छत्तीसगढ़ में कृषि क्षेत्र के 537 लोगों ने आत्महत्या की। ये तमाम आत्महत्याएं क़र्ज़ के कारण, अकारण किसानों की रकबा कटौती समेत ऐसे तमाम लालफीताशाही के कारण हुए हैं।

कांग्रेस सरकार के आते ही पहले सत्र से ही किसानों के साथ बर्बरता, उन्हें जेल भेजने समेत तमाम प्रताड़नाओं का दौर शुरू हो गया था। जबकि तथ्य यह है कि किसानों से बड़े-बड़े वादे कर ही कांग्रेस की यह सरकार सत्ता में आयी है। अभी सांसद राहुल गांधी के अल्प प्रवास के दौरान प्रदेश में आंदोलनरत किसानों पर टूट कर पुलिसिया बर्बरता का दौर चला। आश्चर्य तो यह है कि यूपी के लखीमपुर तक में वोट के लिए दौड़ पड़ने, वहां जा कर छग के खजाने से करोड़ों मुआवजा बांट आने वाली भूपेश सरकार अपने ही किसानों के साथ ऐसे पेश आती है। कथित किसान आन्दोलन में कथित रूप से 700 किसानों की मौत का झूठ परोसने वाली कांग्रेस, अपनी ही सरकार के कृषि विभाग के आंकड़े झुठलाते हुए कहती है कि वह किसानों की आत्महत्या के आंकड़े नहीं रखती, इससे अधिक दुर्भाग्य की बात और क्या होगी भला? बहरहाल।

तमाम अव्यवस्थाओं और धोखधड़ी, वादाखिलाफी आदि का रिकॉर्ड बना कर प्रदेश में धान खरीदी की प्रक्रिया पूरी हुई। जहां भाजपा की सरकार में श्री भूपेश बघेल 1 नवम्बर से धान खरीदी के लिए आन्दोलन चलाते थे, वहां खुद की सरकार में जान-बूझ कर, विपक्ष द्वारा बार-बार याद दिलाने के बावजूद एक महीने विलंब से धान खरीदी शुरू की गयी। इस कारण बेमौसम बारिश से किसानों की तैयार फसल खेत में ही चौपट हो गयी। यहां नियम यह है कि चाहे आप जितना धान उपजाएं लेकिन राज्य सरकार केवल 15 क्विंटल धान लेगी। जबकि

धान खरीदी की मियाद बढ़ाने समेत अन्य मांगों को लेकर धरनारत किसान।

राहुल गांधी साफ़-साफ़ वादा कर गए थे कि ऐसी कोई लिमिट नहीं रहेगी। फिर भी शासन द्वारा बेशर्मी से अपने वादे से मुकरने के कारण भी किसानों में निराशा व्याप्त है। इसी सत्र में सुरेश नेताम तो इससे पहले धनीराम मरकाम जैसे किसानों की आत्महत्या की खबर शासन के लाख दबाने के बाद भी सुर्ख़ियों में रहे।

तमाम लेटलतीफी और झंझटों के बाद भी अपने ही लक्ष्य से शासन 8 लाख टन से अधिक धान खरीदने से पीछे रही। अर्थात शासकीय आकलन के अनुसार ही इस बार कम से कम 2 हज़ार करोड़ रूपये का धान किसान नहीं बेच पाए भाजपा लगातर इस दो हज़ार करोड़ के रकम की भरपाई करने की मांग भी सरकार से कर रही है। अगर सरकारी लक्ष्य से अलग की बात करें तो इस वर्ष पूरे प्रदेश में 30 लाख 26 हजार सात सौ बाइस हेक्टेयर रकबा का पंजीयन किया गया था। जिसके हिसाब से 112 लाख मैट्रिक टन धान की खरीदी किया जाना था किंतु सरकार अपने द्वारा निर्धारित किए गए लक्ष्य 105 लाख मैट्रिक टन के बराबर भी धान खरीदी नहीं कर पाई जो किसानों के साथ धोखा है। पूरे प्रदेश में 24 लाख किसान पंजीकृत थे जिनमें से लगभग ढाई लाख किसानों को एक बार भी टोकन नहीं मिल पाया तथा ढाई लाख किसानों को दूसरा और तीसरा टोकन नहीं मिलने के कारण वे अपनी उपज को औने पौने दर में बेचने मजबूर हैं। इस प्रकार पंजीकृत रकबा के हिसाब से लगभग 15 लाख मि० टन किसानों का धान सरकार नहीं खरीद पाई। जिससे कर्ज के बोझ से लदे किसान आत्महत्या कर रहे हैं और कुछ अपनी उपज को औने पौने दर पर बेचने के लिए मजबूर हो रहे हैं। यह रकम करीब 5 हज़ार करोड़ के आसपास का होता है।

इन तमाम परेशानियों से बेपरवाह सीएम बघेल चुनावी राज्यों में वोटों की फसल उगाने की नाकाम कोशिशों में व्यस्त हैं। प्रदेश के किसान आंदोलनरत हैं, खाद की कालाबाजारी के कारण भी उसकी किल्लत उफान पर है। मंडी टैक्स माफ़ करने का वादा कर सत्ता में आने के बावजूद टैक्स डेढ़ गुना बढ़ा दिया गया है। वादे अनुसार दो साल का बोनस भी किसानों का बकाया है ही।

इधर किसान तमाम तरह के छल का दंश झेलते हुए भी अगली फसल की तैयारी में व्यस्त हैं, उधर सीएम बघेल कांग्रेस की दृष्टि से बंजर हो चुकी यूपी की भूमि पर छत्तीसगढ़ के संसाधनों से प्रियंका-राहुल के लिए हल जोतने और हल तलाशने में भी लगे हुए हैं। छत्तीसगढ़ की परवाह करने की ज़रूरत क्यों हो आखिर उन्हें? ढाई साल की जंग जो जो अब उन्होंने जीत ली है! •

प्रतिक्रिया कृपया इस आईडी पर दें-
jay7feb@gmail.com

प्रेरक और सदैव प्रासंगिक दीनदयाल

डा. शिव शक्ति बक्सी

जिस समाज और धर्म की रक्षा के लिए श्रीराम ने वनवास सहा, श्रीकृष्ण ने अनेक कष्ट उठाये, महाराणा प्रताप जंगल-जंगल फिरे, शिवाजी ने सर्वस्व अर्पण कर दिया, गुरु गोविंद के बच्चे जीते जी किले की दीवारों में चुने गये, क्या उसकी खातिर हम झूठी आकांक्षाओं का त्याग भी नहीं कर सकते? ये पंक्तियां पंडित दीनदयाल उपाध्याय द्वारा अपने मामा को 21 जुलाई,1942 को लिखे एक पत्र का अंश हैं। तब उनकी आयु 26 वर्ष थी। इससे पांच वर्ष पहले वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संपर्क में आये। युवा दीनदयाल अंग्रेजी शासन के आर्थिक दुष्परिणामों के साथ-साथ उसकी सांस्कृतिक एवं सभ्यतागत चुनौतियों को भी समझते थे। राष्ट्र के सर्वांगीण विकास की आवश्यकता पर बल दिया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय एकात्म मानव दर्शन के प्रतिपादक के रूप में ख्यात हैं।

उन्होंने राष्ट्र को आक्रांत करनेवाली समस्याओं के अलग-अलग समाधान खोजने के दृष्टिकोण का समर्थन नहीं किया, बल्कि उनकी आकांक्षा एक ऐसे दर्शन का सृजन करने की थी, जो एकात्म दृष्टिकोण के युग का सूत्रपात कर सके। उन्होंने भारत की सभ्यता और सांस्कृतिक लोकाचार की भाषा में राष्ट्रीय विमर्श के प्रचलन पर जोर दिया। वे पश्चिमी विचारों के पक्ष में नहीं थे। उनका मानना था कि पूंजीवाद व साम्यवाद मनुष्य के लोकतांत्रिक अधिकारों के विरुद्ध हैं।

पंडित दीनदयाल उपाध्याय के मुख्य विचार भारतीयता, धर्म, धर्मराज्य और अंत्योदय की उनकी अवधारणाओं में देखे जा सकते हैं। उनका मानना था कि 'राष्ट्रीय दृष्टिकोण से हमें अपनी संस्कृति पर विचार करना होगा क्योंकि वही हमारी मूल प्रकृति है।' वे 'धर्म' को 'रिलिजन' के रूप में व्याख्यायित करने के प्रयास के विरोधी थे। उनके अनुसार, 'रिलिजन' का मतलब एक पंथ या एक वर्ग है, जबकि 'धर्म' एक व्यापक अवधारणा है तथा जीवन के सभी पहलुओं के साथ संबद्ध है।

'धर्मराज्य' का वर्णन करते समय वे राज्य को राष्ट्र के भीतर एक घटक मानते हैं, राष्ट्र के ऊपर नहीं। ऐसा करते हुए उनका इरादा समाज या लोकतंत्र में राज्य के महत्व को कम करना नहीं था, बल्कि समाज और राष्ट्र के बहुलतावादी चरित्र पर जोर देने का प्रयास है। अंत्योदय हालांकि गांधीवादी शब्दकोश से संबंधित शब्द है, जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय के विचारों में अंतर्निहित है। आर्थिक लोकतंत्र के अपने विचार की व्याख्या करते हुए वे कहते हैं, 'अगर हर किसी के लिए एक वोट राजनीतिक लोकतंत्र का पारस पत्थर है, तो हर किसी के लिए काम आर्थिक लोकतंत्र का एक सिद्धांत है। इस काम के अधिकार का मतलब दास श्रम नहीं है, जैसा कि साम्यवादी देशों में माना जाता है।' बड़े पैमाने के उद्योगों पर आधारित विकास, केंद्रीकरण और एकाधिकार के विचारों का विरोध करते हुए उन्होंने स्वदेशी और विकेंद्रीकरण की वकालत की। उन्होंने महसूस किया है कि भारत के लिए मार्ग स्वरोजगार से होकर निकलता है, जिसमें अधिकतम उत्पादन अधिकतम हाथों को रोजगार देकर किया जा सकता है। वे एकात्म ग्राम के पक्के समर्थक थे।

पंडित दीनदयाल उपाध्याय के वैचारिक ढांचे में भारतीय राजनीति के आध्यात्मीकरण के साथ ग्राम स्वराज की स्थापना के माध्यम से विकेंद्रीकरण तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था और समाज के पुनरोद्धार पर जोर दिया गया है

स्वामी विवेकानंद, महर्षि अरविंद, तिलक, गोखले, गांधी जैसे महान विचारकों ने औपनिवेशिक युग में देश को नेतृत्व प्रदान किया, तो डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, डॉ राममनोहर लोहिया और जयप्रकाश नारायण ने स्वातंत्र्योत्तर काल में राष्ट्रीय पुनर्निर्माण के लिए नये कार्यक्रमों की कल्पना की और लोगों को संगठित किया।

सुशासन और विकास के विचार को भारतीय वास्तविकता के संदर्भ में अवधारित करने की आवश्यकता है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के वैचारिक ढांचे में भारतीय राजनीति के आध्यात्मीकरण के साथ ग्राम स्वराज की स्थापना के माध्यम से विकेंद्रीकरण तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था और समाज के पुनरोद्धार पर जोर दिया गया है। वे गरीबों में सबसे गरीब के लिए सबसे अधिक चिंता दिखाते हैं तथा खुद को सर्वोदय और अंत्योदय के लक्ष्यों के लिए प्रतिबद्ध करते हैं। उनकी दृष्टि 'सहभागी लोकतंत्र' की है, जिसमें प्रमुख रूप में दक्षता व प्रभावशीलता के साथ पारदर्शिता, जिम्मेदारी और जवाबदेही मौलिक तत्व हैं। वास्तव में ये तत्व भारतीय सभ्यता और सांस्कृतिक लोकाचार और परंपराओं के आवश्यक घटक हैं, जो संस्कृति, समाज और राज्य के प्रमुख सिद्धांतों के रूप में मान्य हैं।

वर्तमान में जब आपा-धापी और प्रतिस्पर्द्धा की चुनौतियों के बीच युवाओं के मौलिक विकास एवं उन्हें स्वतंत्र भारत के सांस्कृतिक स्तंभ के रूप में स्थापित करने की आवश्यकता महसूस की जाती है, तब दीनदयाल जी का व्यक्तित्व एक आदर्श के रूप में सामने आता है। राजनीति में गंभीर, विचारशील, सिद्धांतवादी एवं ध्येयनिष्ठ कार्यकर्ता एवं राजनेता होने का जो उदाहरण उन्होंने प्रस्तुत किया, उससे युवा वर्ग प्रेरित होता रहेगा। आज प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में उनके सुझाये समाधान के मार्ग के अनुरूप सरकार द्वारा उठाये गये कदमों से भारत की तस्वीर बदलने लगी है। ऐसे समय में पंडित दीनदयाल उपाध्याय के विचार मार्गदर्शक बनकर युवाओं का पथ प्रशस्त कर रहे हैं। •

स्मृति शेष

असली छत्तीसगढ़ियावाद के विशिष्ट ध्वजवाहक दाऊ आनंद कुमार

अनिल पुरोहित

समृद्धि के वैभव को त्यागकर संघर्ष और तपस्या की राह पर चलने वाले बिरले ही होते हैं और इतिहास वे ही बनाते हैं, इतिहास उनका ही होता है। छत्तीसगढ़ की पुण्यधरा पर जन्म लेकर इसकी माटी का कर्ज़ चुकाने के लिए अपने जीवन का क्षण-क्षण न्यौछावर करने वाली महान विभूतियों की सुदीर्घ मणि-माला है। उन सभी तपःपूतों का जीवन यह सत्य स्थापित करता है कि एक विचार के लिए सम्पूर्ण जीवन समर्पित कर देना कितना कठिन है। कहते हैं, रोज स्नान करने वाले लिबास ही बदलते हैं, स्वेद (पसीना) से नहाने वाले तो इतिहास बदलते हैं। संपन्नता के मोहपाश को काटकर संघर्ष के रास्ते चलकर इतिहास में अपने विचार के लिए सतत समर्पित दाऊ आनंद कुमार छत्तीसगढ़ के कोने-कोने तक अपनी पहचान ख़ुद ही गढ़ने वाली ऐसी ही एक शख़्सियत थे, जिन्हें हाल ही हमने सदा-सर्वदा के लिए खोया है।

अपने ज़माने के भारतीय जनसंघ के धाकड़ नेता रहे स्व. दाऊ जी आपातकाल में मीसा के तहत जेल भी गए। बाद में छत्तीसगढ़ को भय-भूख-भ्रष्टाचार और शोषण से मुक्त कराना उनका ध्येय बन गया और इसके लिए वे पृथक छत्तीसगढ़ राज्य के लिए आंदोलन करने लगे। आज से 50 साल पहले छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के लिए दिल्ली, भोपाल और फिर रायपुर में उन्होंने अखंड धरना अभियान शुरू किया था। इस दौरान स्व. दाऊजी पूरे छत्तीसगढ़ का दौरा करते और पृथक राज्य के वातावरण बनाने में अहर्निश जुटे रहते। छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के लिए संघर्षरत व समर्पित रहे दाऊ आनंद कुमार जी का निधन छत्तीसगढ़ राज्य के लिए अपूरणीय क्षति है। छत्तीसगढ़ राज्य के संघर्ष-पुरुष और प्रणेता के रूप में वे हमेशा याद रखे जाएंगे, जिन्होंने अपना पूरा जीवन, धन और सृजन छत्तीसगढ़ राज्य की कल्पना और निर्माण के लिए समर्पित किया।

दाऊ जी का जाना उस पीढ़ी का चला जाना है, जिसने छत्तीसगढ़ निर्माण के लिए अपना खून-पसीना एक कर दिया लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि कांग्रेस ने उन्हें उन्हें उपेक्षित रखा। इस बात का उन्हें मलाल तो रहता था, लेकिन वह अपना काम करते रहे। प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार श्री रमेश नैयर जी स्व. दाऊ आनंद कुमार के जीवन-प्रसंगों का स्मरण करते हुए बताते हैं कि सन् 1974 से दिल्ली, भोपाल और रायपुर में निरंतर और अखंड धरना देकर उन्होंने राज्य निर्माण की मांग की। छत्तीसगढ़ के प्रति उनका समर्पण अतुल्य, अविस्मरणीय और अद्वितीय था। श्री नैयर भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष रहे बच्छराज व्यास जी के नेतृत्व में चले आंदोलन में दाऊ आनंद जी के साथ अपनी जेल यात्रा का स्मरण कर उन्हें अद्वितीय और सरोकारी व्यक्तित्व का धनी कहते हैं।

जिन्होंने स्व. दाऊ जी के संघर्ष, त्याग और तपस्या का साक्षात्कार किया है, वे सभी लोग 'छत्तीसगढ़िहा-वाद' का झंडा ताने घूम रहे छत्तीसगढ़ के मौजूदा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को कभी इसलिए माफ़ नहीं करेंगे क्योंकि प्रदेश के कांग्रेसी तुग़लक़शाहों ने अपनी सनकमिज़ाजी के चलते एक झटके में मीसाबंदियों को भाजपा शासनकाल से दी जा रही सम्मान निधि बंद कर दिया। ऐसा करके स्व. दाऊ जी और उनके जैसे असंख्य लोकतंत्र व छत्तीसगढ़ के सेनानियों को मुफ़लिसी और गुमनामी की अंधी गलियों में धकेल दिया गया था। इतिहास साक्षी है कि इस देश की जनता को कांग्रेस सरकार ने 1975 में दोबारा ग़ुलाम बना दिया था। देश में 19 माह आपातकाल लागू रहा। हज़ारों लोग जेलों में ठूंस दिए गए थे। फिर जनता पार्टी की सरकार बनी और बहुत बाद में छत्तीसगढ़ में और मध्यप्रदेश में भाजपा की सरकार आई तो उन्होंने सभी मीसाबंदियों को पेंशन देना शुरू किया। लेकिन पिछले तीन सालों से यह पेंशन बंद कर दी गई थी क्योंकि अब यहां उस कांग्रेस की सरकार है जिसने आपातकाल लागू किया था।

कांग्रेस सरकार को अब आत्ममंथन करना चाहिए कि उसने ऐसा करके इस देश की उस पीढ़ी के साथ अन्याय किया है जो दूसरी आज़ादी के लिए संघर्ष कर रही थी। ये लोग इसी देश के नागरिक थे, जो लोकतंत्र की रक्षा के लिए जेल गए। इसलिए आपातकाल की लड़ाई को दूसरी आज़ादी का नाम दिया गया। लेकिन जबसे कांग्रेस की सरकार आई है, मीसा बंदियों की पेंशन बंद कर दी गई। इस कारण अनेक लोग आर्थिक संकट से गुजरने लगे। उनमें से ही एक शख्स थे दाऊ आनंद कुमार, जो 5 जनवरी 2022 को आर्थिक परेशानी झेलते हुए परलोक सिधार गए।

छत्तीसगढ़ के मौजूदा मुख्यमंत्री बघेल समेत तमाम तुग़लक़ी सत्ताधीशों के ऐसे पाखंड की जितनी लानतें दी जाएं, कम ही होगी। मीसा बंदियों की सम्मान निधि रोके जाने के प्रदेश की कांग्रेस सरकार के ख़िलाफ़ हाई कोर्ट के हर फ़ैसले व आदेश को ताक पर रखने की कांग्रेस के तुग़लक़ों ने हरसंभव धृष्टता की, पर अंततः हाई कोर्ट ने न केवल सम्मान निधि जारी रखने का आदेश दिया, अपितु जबसे यह राशि रोकी गई, तबसे अब तक की पूरी राशि का भुगतान उनको करने के लिए प्रदेश सरकार को आदेश भी किया।

हाई कोर्ट का यह फ़ैसला धनाभाव में बीमारी से जूझते हुए परलोक सिधार गए स्व. दाऊजी के प्रति श्रद्धांजलि ही है। प्रदेश के वरिष्ठ साहित्यकार व व्यंग्यकार श्री गिरीश पंकज ने स्व. दाऊ को श्रद्धांजलि देते हुए उनकी आर्थिक बदहाली और मीसा पेंशन बंद करने के कांग्रेस के इस पाखंड का मार्मिक जिक्र हाल में लिखे एक लेख में किया है।

मीसाबंदी सम्मान निधि (पेंशन) बंद करने के कारण स्व. दाऊजी की आर्थिक स्थिति काफी खराब हो गई। वे कुकुरबेड़ा नामक इलाके में एक बहुत साधारण-से घर में रहने लगे लेकिन उसके बाद भी सामाजिक जागरण के काम करते रहे। उन्होंने आर्य समाज संस्था के माध्यम से विवाह कराने का भी कार्यक्रम शुरू किया। बाद में वह भी किसी कारण बंद हो गया। पिछले एक-दो सालों से वे संत बालक दास पीठ की स्थापना कर वे उनका मंदिर बनवाने के काम में लगे हुए थे। वे प्रायः समाजसेवी सरदार मनमोहन सिंह सैलानी के साथ बैठकर अनेक वैचारिक संगोष्ठियों में शिरक़त किया करते थे। दाऊजी ने रायपुर में खंडपीठ की मांग को लेकर भी वर्षों तक धरना दिया था। उनसे मिलकर बड़ा हौसला मिलता था। तमाम विपरीत परिस्थितियों में भी उनके भीतर जीने का जज्बा बना हुआ था। भारतीय जनसंघ के सशक्त झंडाबरदार रहे, छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के लिए सतत संघर्षरत और निर्माण के बाद भी असली छत्तीसगढ़ियावाद का झंडा बुलंद किये रहे दाऊ जी को भाजपा परिवार की विनम्र श्रद्धांजलि। •

हिजाब या अलगाववादी षडयन्त्र

विनोद बंसल

भारतीय संविधान के अनुसार प्राथमिक शिक्षा सबके लिए अनिवार्य है। किन्तु इस अनिवार्यता के बावजूद दुर्भाग्यवश स्वतंत्रता के 75वें वर्ष में भी देश की कुल जनसंख्या का 36.90 फीसदी हिस्सा आज भी निरक्षर है। मुस्लिमों में तो यह निरक्षरता दर 42.7 फीसदी है। यदि महिलाओं की बात कर तो ये आंकड़े और भी भयावह हैं। देश की 66 प्रतिशत मुस्लिम महिलाएं आज भी निरक्षर हैं। उच्च शिक्षा में तो इनकी भागीदारी मात्र 3.56 प्रतिशत ही है जो कि अनुसूचित जातियों के अनुपात 4.25 प्रतिशत से भी कम हैं।

क्या कभी सोचा है कि ये सब आखिर क्यों है? स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात एक तो हमारे राजतन्त्र की शिक्षा के प्रति उदासीनता, दूसरा संसाधनों का अभाव तथा ऊपर से धार्मिक कट्टरता ने मुस्लिम महिलाओं की साक्षरता दर को सबसे नीचे रखा। पहले तो बेटियों को घर से ही नहीं निकलने दिया जाता। दूसरा उन पर बुर्के को लाद दिया जाता है। अकेले घर से बाहर पांव नहीं, मोबाइल नहीं, श्रृंगार नहीं, मनोरंजन नहीं, पर-पुरुष से बात नहीं, इत्यादि अनेक फतवे थोप दिए जाते हैं। जिसके कारण पहले तो उनके परिजन ही विद्यालय नहीं भेजते और यदि ऐसा हो भी जाए तो ये बंधन बेटियों के पाँवों को बेड़ियों की तरह जकड़े रहते हैं।

'बेटी-बचाओ, बेटी पढ़ाओ' अभियान के अंतर्गत वर्तमान केंद्र सरकार ने अपनी विभिन्न योजनाओं के माध्यम से बेटियों की शिक्षा के लिए विशेष प्रयास प्रारंभ किए। जिसका प्रतिफल बेटियों की सुरक्षित व सहज शिक्षा के रूप में सामने आ रहा है। आज चारों ओर के परीक्षा परिणामों पर नजर डालें तो बेटियां सर्वाधिक अंक प्राप्त कर मेरिट में सबसे ऊंचे पायदान पर दृष्टिगोचर हो रही हैं। यह एक सुखद अनुभूति तो है किन्तु अभी जब हम लक्ष्य से कोसों दूर हैं तभी अचानक उन बेटियों की शिक्षा पर अचानक कुछ कट्टरपंथियों का पुनः आक्रमण पीड़ादायी लगता है।

अचानक विरोध क्यों

2022 के प्रथम माह में ही कर्नाटक में उडुप्पी के एक छोटे से स्कूल में प्रारम्भ हुआ अनावश्यक विवाद, जिहादियों या यूं कहें कि कुछ कट्टरपंथियों की हठ के चलते कुछ ही दिनों में बागलकोट में पत्थरबाजी तक कैसे बदल गया जहां के स्थानीय प्रशासन को वहां धारा 144 तक लगानी पड़ी।.... राज्य सरकार को अपने सभी शिक्षण संस्थान तीन दिन के लिए बंद करने पड़े।

बच्चों के विवाद में सर्वप्रथम राहुल गांधी कूदे जिन्होंने इसको मुस्लिम व महिला अधिकारों से जोड़ने की कुचेष्टा की। उसके बाद मंगलवार को कर्नाटक के प्रदेश कोंग्रेस अध्यक्ष डी के शिवकुमार ने एक झूठे ट्वीट के द्वारा हिन्दूओं पर आरोप लगाया कि उन्होंने एक कॉलेज में तिरंगे को उतारकर भगवा लहरा दिया जो तिरंगे का अपमान है। जबकि, उसी दिन शिवमोगा के ही पुलिस अधीक्षक बीएम लक्ष्मी प्रसाद ने साफ तौर पर कहा कि पोल पर तिरंगा था ही नहीं। इसमें तिरंगे का अपमान कहां से हुआ। वास्तव में तो कांग्रेस की चिढ़ भगवा और भगवा-धारियों से है। यह एक बार पुनः स्थापित हो गया। हिजाबियों की तरफ से न्यायालय में कांग्रेसी ही तो लड़ रहे हैं। वरिष्ठ कांग्रेसी नेता कपिल सिब्बल तो शुक्रवार को इस मामले को लेकर सर्वोच्च न्यायालय ही पहुंच गए जैसे कि वे तीन तलाक व बाबरी के लिए लड़े। इसके अतिरिक्त इस्लामिक जिहादियों व कथित सेकलक्यूलरिस्टों की टूल किट गैंग द्वारा भी पूरे देश में अराजकता का वातावरण निर्मित किया जा रहा है।

उडुपी की ये छात्राएं गत अनेक वर्षों से उसी विद्यालय में बिना किसी शिकायत के शांति से पढ़ रही थीं। फिर जिस विद्यालय में अचानक हिजाब का उदय हुआ वह तो था ही सिर्फ छात्राओं का जहां, लड़कों का प्रवेश ही वर्जित है। तो फिर हिजाबी पर्दा किस से और क्यों?

इस सारे षड्यंत्र के पीछे देश की उस कट्टर इस्लामिक जिहादी संस्था पीएफआई की उपस्थिति भी साफ तौर पर स्पष्ट हो चुकी है जिसके विरुद्ध अलगाववादी व आतंकवादी गतिविधियों के संदर्भ में देश की सर्वोच्च सुरक्षा एजेंसी - एनआईए जांच एजेंसी जांच कर रही है और जो देशभर में इस्लामिक कट्टरता और अराजकता फैलाने में लिप्त है। इसकी छात्र विंग कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया का बयान भी मीडिया में आ चुका। यह संयोग है या षड्यंत्र, ये आप तय करें किन्तु यह तथ्य और सत्य है कि जैसे ही कॉंग्रेस ने कट्टरपंथियों की चाल के समर्थन में ट्वीट करना प्रारम्भ किया पाकिस्तान से भी उसी स्वर में अनेक तालियां बजने लगीं। एक ओर जहां कभी कट्टरपंथियों का विरोध व विद्यार्थियों का समर्थन करने वाली पाकिस्तानी नोबल विजेता मलाला, जिसने हलाला पर भी कभी मुंह नहीं खोला, हिजाब का हिसाब मांगने लगी। इतना ही नहीं, पाकिस्तान के अनेक मंत्री, नेता व वहां की पूर्व प्रधानमन्त्री की बेटी भी इस हिजाब जिहाद की समर्थक बन ट्वीट पर टूट पड़ीं। कॉंग्रेस के ट्वीट पर पाकिस्तान ताली ना बजाए ऐसा कैसे हो सकता था! खैर! अब सीबीएसई ने अपनी फाइनल परीक्षाओं की तिथि घोषित कर दी है। आगामी 26 अप्रेल से वे परीक्षाएं देश भर में होने वाली हैं। अब विद्यार्थियों को स्वयं को राजनीति या कट्टरपंथियों का मुहरा बनने की बजाय अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। गणवेश तो पहनना ही पड़ेगा इसी में सब की भलाई भी है। हम 21वीं सदी के नागरिक हैं।

हम एक-एक बेटी को शिक्षित व जागरूक नागरिक बनाएंगे चाहे वे किसी भी मत-पंथ, संप्रदाय, भाषा-भूषा या क्षेत्र की हो। •

लेखक विश्व हिन्दू परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं

आरक्षण विरोधी एजेंडा चला रही है कांग्रेस

विष्णुदेव साय

प्रदेश की कांग्रेस सरकार अब शिक्षा विभाग में आरक्षण रोस्टर से पदोन्नति की प्रक्रिया नहीं अपनाकर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के शिक्षकों के साथ छल-कपट करके अन्याय कर रही है। इस मांग को लेकर आरक्षण बचाओ संघर्ष मोर्चा के बैनर तले आहूत आंदोलन के प्रति भाजपा पूर्ण समर्थन व्यक्त करती है। सवाल है कि प्रदेश सरकार हर वर्ग को कोरोना संक्रमण के फैलाव के बावजूद अपने हक और इंसाफ के लिए सड़क की लड़ाई लड़ने के लिए विवश करके आखिर किस बात की दुश्मनी भंजा रही है? जब हाई कोर्ट में मामला लंबित है उसके बावजूद भी भूपेश बघेल सरकार को इतनी जल्दबाजी क्यों है कि वह फैसला आने के पहले पदोन्नति प्रक्रिया को खत्म करना चाह रही है। ऐसी क्या मजबूरी है?

प्रदेश के शिक्षा विभाग में 40 हजार पदों पर पदोन्नति का काम प्रक्रिया में है, लेकिन इस पदोन्नति के लाभ से अजा-जजा वर्ग के कार्यरत लोगों को वंचित करने का काम यह प्रदेश सरकार कर रही है। इसके चलते सभी शिक्षक संवर्ग कर्मियों के साथ-साथ अधिकारी-कर्मचारी और सामाजिक संगठनों में बेहद आक्रोश है। पदोन्नति की इस प्रक्रिया में सहायक शिक्षकों को शिक्षक व प्रथमिक शाला के प्रधानपाठक, व्याख्याता और मिडिल स्कूल प्रधानपाठक के तौर पर पदोन्नत किया जाना है। इसमें आरक्षण रोस्टर पद्धति नहीं अपनाए जाने से सामने आए आक्रोश के बाद अजा-जजा वर्ग से जुड़े सभी संगठनों ने इस पदोन्नति पद्धति का मुखर विरोध कर रहा है। इन संगठनों द्वारा प्रदेश सरकार और संबंधित मंत्री को उक्त पदोन्नति प्रक्रिया पर रोक लगाने के दिए गए आवेदन पर इस नाकारा प्रदेश सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया।

प्रदेश की कांग्रेस सरकार अजा-जजा वर्ग के हितों की रक्षा की शेखी तो खूब बघारती रहती है, लेकिन जमीनी तौर पर वह इन वर्गों के साथ घोर अन्याय करके अपने अजा-जजा विरोधी राजनीतिक चरित्र का निर्लज्ज प्रदर्शन कर रही है।

भाजपा अजा-जजा वर्ग की इस लड़ाई में उनके साथ खड़ी है और इन वर्गों के साथ प्रदेश सरकार द्वारा किसी भी तरह के अन्याय का मुखर विरोध करके पदोन्नति में आरक्षण रोस्टर को लागू कराया जाएगा। प्रदेश की कांग्रेस सरकार एक तरफ तो आरक्षण की वकालत करती है और दूसरी तरफ अपने दोहरे राजनीतिक चरित्र का परिचय देकर पर्दे के पीछे आरक्षण विरोधी एजेंडा चलाकर जरूरतमंदों का हक छीनकर संविधान की भावना को लहूलुहान कर रही है। कोरोना काल को देखते हुए अजा-जजा वर्ग की इस न्यासंगत मांग पर संवेदनशील पहल करके समाधान ढूंढ़े और अजा-जजा वर्ग के साथ हो रहे अन्याय का परिमार्जन करे। •

फोटो साभार

हम भारत के लोग...

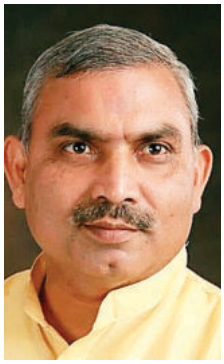

शिव प्रकाश

देश ने 26 जनवरी 1950 को अपना संविधान स्वीकार किया। संविधान स्वीकृति के बाद हम गणतांत्रिक देश बन गये। देश की भौगोलिक, सामाजिक एवं आर्थिक विषमताओं को ध्यान में रखते हुए हमारे संविधान निर्माताओं ने भविष्य में देश के सम्मुख आने वाली चुनौतियों का समाधान करने में सक्षम संविधान देश को दिया। संविधान की प्रस्तावना का प्रारम्भ करते हुए उन्होंने 'हम भारत के लोग' कहा। हम भारत के लोग अर्थात अब हम स्वतंत्र, सम्प्रभुता सम्पन्न गणतंत्र हैं। अब हम किसी विदेशी सत्ता के अधीन नहीं है। हमारा संविधान भी किसी विदेशी सत्ता द्वारा निर्देशित एवं निर्मित नहीं हैं। यह संविधान हमारे प्रतिनिधियों द्वारा अर्थात हमने ही बनाया है। इसका अर्थ है हमारे द्वारा, हमारे लिए जिसको हम स्वीकार अथवा आत्मार्पित कर रहे है।

'हम भारत के लोग' देश के स्वतंत्र होते समय लगभग 40 करोड़ जो अब बढ़कर लगभग 138 करोड़ हो गये हैं। अब हम ही अपने भाग्य के निर्माता है। प्राचीन समय से अपने देश में एक कहावत प्रचलित है कि 'यथा राजा तथा प्रजा'। स्वतंत्रता से पूर्व हमारे देश में राजतंत्र था। राजपरिवार से राजा चुना जाता था। राजा की नीतियों का अनुसरण प्रजा के करने के कारण 'यथा राजा तथा प्रजा' की यह कहावत प्रचलित हुई होगी। स्वतंत्रता के पश्चात हमने लोकतंत्र स्वीकृत किया जिसके परिणामस्वरूप जनता के वोट से जन प्रतिनिधि चुने जाने लगे। चुने हुए जनप्रतिनिधियों के संख्या बल से बहुमत प्राप्त दल, सरकार का गठन करता है। अतः अब हम अपना प्रतिनिधि स्वयं चुनते है। इस कारण जैसा चयन हम करेंगे वैसा हमारा प्रतिनिधि होगा। इसलिए कहावत को ऐसा भी कहा जा सकता है कि 'यथा प्रजा तथा राजा'। इस कारण देशहित का विचार करके मतदान करने वाला समाज गढ़ना देश के अग्रणी लोगों का प्रमुख कार्य है। पं. दीनदयाल उपाध्याय जी ने इस कार्य को 'लोकमन संस्कार' कहा है।

जब हम 'हम भारत के लोग' सम्बोधन करते है तब देश की 138 करोड़ जनसंख्या से इसका सन्दर्भ जुड़ता है। लेकिन 138 करोड़ भारतीयों का मन एवं संस्कार और संस्कार के आधार पर व्यवहार कैसा है, इसका भी विचार करना आवश्यक है। हिमालय से सागर, गुजरात से मणिपुर अर्थात उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम विशाल 38.87 लाख वर्ग किलोमीटर विस्तृत भू-भाग वाला भारत देश है। भागौलिक, जलवायु, मौसम आदि के आधार पर अनेक प्रकार की विविधता के दर्शन यहां पर होते हैं। भाषा के सन्दर्भ में कहा जाता है कि ''कोस-कोस पर बदले पानी, चार कोस पर बानी''। इसी कारण संविधान द्वारा स्वीकृत 22 भाषाएं एवं क्षेत्रीय आधार पर 129 से अधिक बोली बोली जाती हैं। खान-पान, वेशभूषा, जन्म, धार्मिक आस्था, शिक्षा एवं आर्थिक आधार अनेक प्रकार की विविधता निर्माण करते हैं। सतही दृष्टि रखने वाले लोग इन विविधताओं में भेद को देखते हैं।

गुलामी के लम्बे अन्तराल में हम स्वतंत्रता के लिए संघर्षरत रहे। इस कारण गतिशील समाज में अपनी समाज रचना के सन्दर्भ में बार-बार विचार करने की जो आवश्यक्ता रहती है, वह हम नही कर सके। जो समाज व्यवस्था काल बाह्य हो गयी थी, उसका पुनर्विचार भी नहीं हुआ। इस कारण अस्पृश्यता, वर्ण-भेद आदि ने हमारे समाज को जंजीर के समान जकड़ लिया। आज भी जिसके उदाहरण देश में अनेक घटनाओं में प्रकट होते रहते हैं। लक्ष्य से भटकाव अथवा लक्ष्य विहीन समाज होने के कारण हमारी स्वार्थी वृत्ति ने भी अनेक दोष हमारे अंदर उत्पन्न किये। महिलाओं के प्रति दृष्टि अथवा अनेक कुरीतियों का जन्म इसी स्वार्थी मानसिकता का परिणाम है।

जब हम 'हम भारत के लोग' सम्बोधन करते है तब देश की 138 करोड़ जनसंख्या से इसका सन्दर्भ जुड़ता है।

भारत के पास प्राचीन सांस्कृतिक विरासत एवं विश्व को दिशा देने में सक्षम ज्ञान परम्परा है। आर्थिक समृद्धि प्राप्त करने के लिए पर्याप्त कृषि योग्य भूमि, जल एवं वन सम्पदा तथा प्रचुर श्रम शक्ति उपलब्ध है। इन तीनों गुणों के आधार पर हम विश्व की महाशक्ति हो सकते हैं।

जो वैश्विक ताकतें भारत को बढ़ती ताकत के रूप में देखना नहीं चाहती, वह भी भारत को कमजोर करने के लिए भारतीय समाज में विभेदों को बढ़ाने का सुनियोजित प्रयास कर रही हैं। एकात्मता को खंडित करने में कुछ मात्रा में इन लोगों ने सफलता भी प्राप्त की है। गुलामी के कालखंड से ही इन शक्तियों ने भारतीय समाज को कमजोर करने के अनेक प्रयास किये। विभेदों को बढ़ाने के लिए अनेक सिद्धांत गढ़े। उत्तर-दक्षिण, आर्य-द्रविड़, आदिवासी-शहरवासी, भारत एक राष्ट्र नहीं, अनेक राष्ट्रों का समूह, जैसे अनेक सिद्धांत इसी अलगाववादी प्रवृत्ति को बढ़ाने की मानसिकता के उदाहरण है। छोटी-छोटी पहचान को आधार बनाकर आंदोलन खड़े करना एवं अलगाव के बीज बोकर संघर्ष खड़ा करने के प्रयास सुनियोजित तरीके से चल रहे हैं। कुछ समय पूर्व पूना का मराठा-अनुसूचित संघर्ष, सिख-हिंदू संघर्ष के आधार पर आतंक को प्रश्रय, स्पृश्यता-अस्पृश्यता को आधार बनाकर गुजरात एवं उत्तर प्रदेश की घटनाएं

इसी अलगाववादी मानसिकता से उपजे ताजा उदाहरण है। नए-नए सिद्धांतों को गढ़ना, ऐतिहासिक घटनाओं को संदर्भ से काटकर नए-नए संदर्भों में प्रस्तुत करना, छोटे-छोटे विषयों को बढ़ाकर हिंसा फैलाना, हिंसा फैलाने वाले संगठनों को बौद्धिक धरातल देकर संरक्षण करना, ऐसे कार्य करने वालों को समाज में मान्यता प्रदान करना यह एक व्यवस्थित संजाल संपूर्ण देश में फैला है। कभी गरीबी, पिछड़ापन, पर्यावरण आदि का सहारा लेकर कार्य करने वाली शक्तियों को पहचानना आवश्यक है।

'हम भारत के लोग' जब तक परस्पर इतने विभेदों में बंटे रहेंगे एवं अज्ञानतावश अनेक प्रकार के षड़यंत्रों का शिकार बनते रहेंगे तब तक संविधान में व्यक्त संकल्पों की पूर्ति संभव नहीं है। अतः हमें विविधता में एकता को आत्मसात करना होगा। अलग-अलग जातियों, प्रांतों में जन्म लेने के बाद भी एवं अलग-अलग पूजा पद्धतियों में आस्था रखने के बाद भी हम एक ही भारत भूमि की संतान है। यह शस्य-श्यामला भूमि हमारी मां है। मां-पुत्र का यह संबंध हमारे मध्य भाईचारा निर्माण करता है। हमारी सभी की एक साझी विरासत है, हमारी संस्कृति हम को जोड़ती है। समाज सुधारक, अलग-अलग गुणों को आधार मानकर उपदेश देने वाले उपदेशक, भारत की सुरक्षा के लिए बलिदान देने वाले सभी महापुरुष हमारे अपने हैं। हम सभी उनकी संतान हैं।

'हम भारत के लोग' जब तक परस्पर इतने विभेदों में बंटे रहेंगे एवं अज्ञानतावश अनेक प्रकार के षड़यंत्रों का शिकार बनते रहेंगे तब तक संविधान में व्यक्त संकल्पों की पूर्ति संभव नहीं है।

प्रसिद्ध समाजवादी नेता डॉ. राममनोहर लोहिया ने इसी आधार पर कहा था कि इस देश को जोड़ने वाले तत्व 'राम, कृष्ण, शिव' है। हमको इसी एकात्मता के दर्शन करने होंगे। जय-पराजय में प्रकट होने वाली प्रतिक्रिया एवं परिणामों को हम सभी ने समान रूप से भोगा है। विश्व में अपने भारत देश को अग्रणी देश बनाना यह लक्ष्य हम सभी 138 करोड़ भारतीयों को एक दिशा में चलने के लिए प्रेरित करेगा।

हमारे संविधान निर्माताओं ने जब हमको 'हम भारत के लोग' कहकर संबोधित किया, तब इसका संबंध केवल आबादी तक सीमित नहीं होगा। उनकी दृष्टि में एकात्म, समरस, समान लक्ष्य वाला समाज रहा होगा, जिसमें किसी भी प्रकार की विषमता नहीं होगी, समान अवसर एवं सभी को न्याय होगा। जिसका अपना संकल्प, अपना लक्ष्य होगा। गरीबी भगाकर, आर्थिक समृद्धि लाकर एक मन वाला, एक रस समाज जिसमें भारत के प्रति भक्ति, संस्कृति एवं महापुरुषों के प्रति गौरव एवं समान लक्ष्य वाला एक समाज बनाना ही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। विश्व के अग्रणी देशों ने अपने समाज में इन गुणों की वृद्धि कर अपने देश को विश्व में अग्रणी बनाया है।

इस वर्ष देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। गणतंत्र दिवस की शुभ बेला पर इसी विविधता में एकता के दर्शन करते हुए हम अपने संविधान निर्माताओं की आकांक्षा एवं अपने महापुरुषों की इच्छा को पूर्ण करने का संकल्प लें। तभी हम 'हम भारत के लोग' कहलाने के सच्चे अधिकारी होंगे। •

(लेखक भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री हैं)

गणतंत्र दिवस पर दिवस पर प्रदेश भाजपा कार्यालय में समारोह में भाजपा के लोग।

बेरोजगार युवाओं से की गई ठगी के विरुद्ध भाजपा का हल्ला बोल

कांग्रेस अपने अन्य तमाम वादों की तरह ही युवाओं को रोजगार और बेरोजगारी भत्ता देने के वादे से साफ मुकर गई है। कांग्रेस का अब कहना है कि ऐसा कोई वादा उसने किया ही नहीं था। इस विश्वासघात पर समूचे प्रदेश के युवाओं में भारी आक्रोश है। भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ के इन युवाओं के साथ है। प्रदेशाध्यक्ष श्री विष्णुदेव साय ने सीएम को पत्र लिख कर बजट में बेरोजगारी भत्ता के लिए प्रावधान की मांग की है।

प्रति
मा.भूपेश बघेल
मुख्यमंत्री
छतीसगढ़

विषयः- आगामी बजट में युवाओं के लिए जरूरी प्रावधानों बाबत!

मा. मुख्यमंत्री जी,

इन दिनों प्रदेश के आगामी बजट को लेकर तैयारियां चल रही होगी। इस हेतु एक सजग विपक्ष के नाते कुछ बातों पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे।

प्रदेश के पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस पार्टी द्वारा जारी किए गए घोषणा पत्र के बिंदु नंबर 4 में प्रदेश के 10 लाख युवाओं को 2,500 रु प्रति महीने मासिक भत्ता देने का उल्लेख है। इसके अलावा अखबारों में विज्ञापन व बड़े-बड़े होर्डिंग्स के माध्यम से भी 10 लाख युवाओं को भत्ता देने की बात कांग्रेस द्वारा प्रमुखता से कही गयी थी। दुर्भाग्य से पिछले 3 वर्षों के बजट में किसी में। भी बेरोजगारी भत्ता देने हेतु प्रावधान नही किया गया है।

कुछ समय पहले मीडिया रिपोर्ट्स के माध्यम से जानकारी मिली थी कि कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ताओ ने इस हेतु कुछ युवाओं से फार्म भरवाना भी शुरू किया है, परंतु अब तक किसी को भी भुगतान नही किया गया है।इस बात को लेकर प्रदेश में निराशा का माहौल है।

सरकार को अपने वादे के अनुरूप अब 3 वर्षों का प्रति युवा को 90 हजार का भुगतान करना है। भत्ते की राशि 10 लाख युवाओं को प्रतिमाह ढाई हजार के हिसाब से प्रतिवर्ष 3 हजार करोड़ होती है। 3 वर्षों में लंबित राशि 9 हजार करोड़ हो चुकी है।

अतः प्रदेश के युवाओं के लिए नए रोजगार के माध्यम का सृजन करने के साथ-साथ आगामी बजट में उनके भत्ते के लिए कम से कम 9 हजार करोड़ का प्रावधान जरूर करें ऐसा आग्रह है। धन्यवाद।

भवदीय

विष्णु देव साय
प्रदेश अध्यक्ष
भारतीय जनता पार्टी,
छतीसगढ़।

बेरोजगार युवाओं के साथ मजाक कर रही है कांग्रेसः पाण्डेय

सांसद संतोष पाण्डेय ने कहा कि रोजगार के कथित आंकड़ें पेश कर महाझूठ बोलकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बेरोजगारों युवाओं के साथ भद्दा मजाक किया है। भूपेश ने शायद शराब की होम डिलीवरी पहुंचाने वालों को, तो जोड़ लिया है। रेत व खनिज की अवैध

खनन तस्करी में शामिल लोग भी उनकी गिनती में है क्या? या वे 5 लाख नौकरी असम, यूपी में तो नहीं बांट के आ गए? 14000 से ऊपर शिक्षक भर्ती लंबित है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार सहायक प्राध्यापक के चयन के बाद भी नियुक्ति पत्र नहीं दे रही है। इन 3 सालों में बेरोजगार युवकों को ढाई हजार रुपए प्रति महीना भत्ता देने का वादा किया था वह भी नहीं दे रहे हैं। बेरोजगार युवा भटक रहे हैं लेकिन प्रदेश की सरकार इसकी सुध लेने के बजाय रोजगार के गलत आंकड़ा प्रस्तुत कर रही है।

नेता प्रतिपक्ष कौशिक ने बस्तर के युवाओं को नौकरी से निकाले जाने पर चिंता व्यक्त की

नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने कहा कि प्रदेश सरकार की मंशा कोरोना बचाव को लेकर स्पष्ट नहीं है। इसलिए बस्तर के

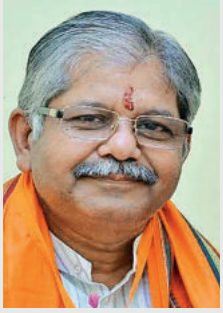

प्रशिक्षित करीब 600 स्वास्थ्य कर्मियों को ऐसे समय पर नौकरी से निकाल दिया है जब उनकी आवश्यकता कोरोना बचाव अभियान में है। इस समय कोरोना के नये वेरिएंट को लेकर जो परिस्थितियां निर्मित हो रही है, उससे बचाव को लेकर स्वास्थ्य कर्मियों की भूमिका अहम है लेकिन उन्हें नौकरी से निकालकर प्रदेश की सरकार क्या साबित करना चाह रही है यह किसी के समझ में नहीं आ रहा है।

छेर-छेरा के रूप में भाजयुमो ने मांगा बेरोजगारी भत्ता और रोज़गार

भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने प्रदेशभर में सोमवार को छेर छेरा पर्व के पावन अवसर पर छत्तीसगढ़ सरकार से छेर छेरा के रूप में 2500 रुपये बेरोजगारी भत्ता और रोजगार कि मांग की। राजधानी रायपुर में भाजयुमो कार्यकर्ताओं ने शास्त्री चौक पर छेर छेरा मांग कर प्रदेश सरकार को जगाने का प्रयास किया। इस दौरान भाजयुमो प्रदेश अध्यक्ष अमित साहू, जिला अध्यक्ष गोविंदा गुप्ता, अमित मैसेरी, उमेश घोरमोड़े, अजय सोनी, विपिन साहू, वैभव ठाकुर, अर्पित सूर्यवंशी, आकाश तिवारी, मुकेश पटेल, वासु शर्मा, हरिओम साहू, सहित भाजयुमो कार्यकर्ता मौजूद रहे। राजधानी सहित प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों व मंडलों में भाजयुमो ने छेर छेरा के रूप में रोजगार व बेरोजगारी भत्ता मांगा और छत्तीसगढ़ के युवाओं की

आवाज बुलंद की। भाजयुमो के प्रदेश अध्यक्ष अमित साहू ने कहा कि छेर छेरा के पावन अवसर पर दान की परंपरा हैं और आज के दिन किसी को भी खाली हाथ नहीं लौटाया जाता और इसी लिए भाजयुमो आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम से राहुल गांधी सहित कांग्रेस पार्टी से और उनकी सरकार से छत्तीसगढ़ के युवाओं का हक छेर छेरा के रूप में मांग रहा हैं। •

राहुल गांधी की गुप्त यात्रा और कांग्रेस का चीन प्रेम!

दीप कमल ब्यूरो

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी की जान पर आये खतरे की काफी बड़ी खबर के बीच चीन से संबंधित एक और बड़ी खबर अधिक स्थान नहीं बना पायी जिसका सरोकार कुछ हद तक कांग्रेस और राहुल गांधी से भी है। खबर गलवान से थी जहां के बारे में खुलासा हुआ है कि वहां पर जिस चीनी कब्जे की खबर राहुल गांधी ने ट्वीट कर उड़ायी थी, वह फर्जी थी। उस खबर को फर्जी वीडियो के माध्यम से चीन ने क्रियेट किया था। वास्तव में गलवान पर कब्जे के कथित समारोह का एक वीडियो चीन ने जारी किया था। उस कथित समारोह का फर्जी वीडियो बनाने में चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ने चीनी एक्टर वू जिंग और उनकी पत्नी शी नान से एक्टिंग कराई थी। ख़बरों के अनुसार उसकी शूटिंग चीन ने गलवान नदी से करीब 28 किलोमीटर पीछे अकसाई चिन में की थी।

नए साल पर चीन ने गलवान में कब्जे से संबंधित ये वीडियो जारी किये थे। उसे चीन के अलावा पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई ने अपनी पूरी ताकत लगा कर प्रसारित किया था। और इन दोनों के अलावा जिस एक व्यक्ति और समूंह ने भारत में पूरी ताकत से उसे प्रसारित किया, वे थे राहुल गांधी और पार्टी जाहिर है कांग्रेस थी! राहुल गांधी ने उस झूठी खबर पर ट्वीट कर अपने ही देश की सरकार को हमेशा की तरह कठघरे में खड़ा किया था। अगर राहुल की यात्रा के बारे में लगाई जा रही अटकलों को नज़रंदाज़ भी कर दें, उनकी हालिया अज्ञात यात्रा में भी इन्हें संदेह का लाभ दे दें, फिर भी परिस्थितिजन्य साक्ष्य ऐसे हैं जो राहुल की देशविरोधी गतिविधियों की तरफ इशारा तो करते ही हैं। चीनी प्रोपगंडा में कांग्रेस के शामिल हो जाने का का यह कोई पहला मामला भी नहीं है। पिछले कुछ वर्षों से खासकर जब से कांग्रेस के हाथ से सत्ता गयी है, नेहरू परिवार और कांग्रेस की चीन को लेकर अनेक गतिविधियां तो अत्यधिक संदिग्ध रही है ही।

जैसा कि आप सभी जानते हैं, समूची लोकतांत्रिक दुनिया में यह मान्य परम्परा है कि जब भी किसी दुश्मन देश से युद्ध की स्थिति हो, तब देश में कोई विपक्ष नहीं होता है। ऐसे मामले में सारा देश और सभी पार्टियां चट्टान की तरह अपनी सरकार के साथ खड़ी रहती हैं, सभी साथ मिलकर अपने सैनिकों का मनोबल बढाते रहते हैं। भारत में भी हमेशा से ऐसा ही होता रहा है। विपरीत से विपरीत हालातों में भी अपने देश की जीत के प्रति आश्वस्त रहना, यह मान्य सिद्धांत और परम्परा भी है। और ऐसा होना उचित भी।

लेकिन गलवान गतिरोध का पिछले वर्षों का मामला याद कीजिये। जब भी वहां या दोकलाम समेत किसी भी जगह कोई विवाद उत्पन्न हुआ, कांग्रेस हमेशा केंद्र सरकार के खिलाफ खड़ी दिखी। एक से एक झूठ गढ़ कर विदेशी मामलों में भी अपनी ही सरकार को बदनाम किया गया। एक स्वर में राहुल गांधी समेत कांग्रेस के लगभग सभी नेताओं ने गलवान में भी भारत की पराजय, देश के सरेंडर की घोषणा कर दी थी। सोश्यल मीडिया प्लेटफार्म्स पर तो बकायदे अभियान चलाये गए। जहां सरेंडर हुए नरेंदर... आदि हैशटैग तक ट्रेंड कराये गए थे। बाकायदा अपने ही चुने गए प्रधानमंत्री को गद्दार आदि बताया गया था।

नए साल पर चीन ने गलवान पर कथित कब्जे से संबंधित वीडियो जारी किये थे। उसे चीन के अलावा पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई ने अपनी पूरी ताकत लगा कर प्रसारित किया था। और इन दोनों के अलावा जिस एक व्यक्ति और समूंह ने भारत में पूरी ताकत से उसे प्रसारित किया, वे थे राहुल गांधी और पार्टी जाहिर है कांग्रेस थी!

कल्पना कीजिये कि ऐसे अभियानों से आखिर किसे लाभ मिल सकता है? ज़ाहिर है दुश्मन देश को ही। है न?

तथ्य महज़ इतने ही नहीं हैं। आप अगर चीन से कांग्रेस के संबंध की अन्य कड़ियां भी जोड़ते जायेंगे तो हालात की भयावहता का अनुमान लगा सकते हैं। याद कीजिये गलवान गतिरोध के समय ही राहुल गांधी की एक और 'गुप्त मीटिंग' जो तब के शीर्ष चीनी राजनयिक के साथ हुई थी। पहले तो कांग्रेस ने ऐसी किसी मीटिंग से साफ़ इनकार किया था लेकिन बाद में साक्ष्य सामने आ जाने पर उन्हें मानना पड़ा कि ऐसी मुलाक़ात हुई थी। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी द्वारा चीन की सत्ताधारी कम्युनिस्ट से सोनिया-राहुल की उपस्थिति में किए गए एमओयू की याद कीजिए। राहुल गांधी की तब के मानसरोवर

फोटो साभार

यात्रा की याद कीजिए।

चीन से इतर की बात भी करें तो कांग्रेस के नेता द्वारा मोदी जी को हराने के लिए पाकिस्तान से मदद मांगने की बात याद कीजिये, पंजाब के कांग्रेस अध्यक्ष द्वारा पाकिस्तान के पक्ष में दिए बयान की याद कीजिये, पाकिस्तान से लगे सीमाई इलाके फिरोजपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ की गयी साज़िश और जश्न मनाने में खालिस्तानियों और कांग्रेस नेताओं के प्रतिक्रियाओं की साम्यता देखिये ... ऐसे तमाम तथ्य जिस अवैध गठजोड़ की तरफ संकेत करते हैं, वह हमारी नींदें उड़ा देने के लिए काफी होना चाहिए। राहत की बात महज़ इतनी है कि देश में प्रखर राष्ट्रभक्त और सशक्त नेतृत्व मौजूद है, जिसके कारण ऐसे कोई भी षड्यंत्र सफल नहीं हो रहे।

विपक्ष में लम्बे समय तक रही भाजपा ने कभी भी दुश्मन देशों के मामले में या कूटनीतिक मामलों में कभी भी देश के सरकार की आलोचना नहीं की। उलटे अपनी सरकार का पक्ष रखने अटल जी विदेश तक गए थे। ऐसे शानदार लोकतांत्रिक इतिहास वाले देश में नेहरू-वाड्रा परिवार द्वारा लगातार की जा रही संदिग्ध हरकतों पर जनता को संज्ञान लेने की आवश्यकता है। देश को सोचना होगा कि क्या हम ऐसे नेताओं को अब सहन करने की स्थिति में हैं? •

निरर्थक डींगें हांकने के अलावा और कुछ नहीं निकला राहुल की यात्रा से : भाजपा

भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने कहा कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का छत्तीसगढ़ दौरा निरर्थक सियासी कवायद और तथ्य-सत्य से आंखें मूंदकर अपनी राजनीतिक अपरिपक्वता का प्रदर्शन भर था। श्री साय ने कहा कि तमाम शिगूफ़ों में क़रारी मात खाने के बाद राहुल गांधी ने एक नया शिगूफ़ा गढ़ा है- अमीर भारत और ग़रीब भारत; और स्थिति यह है कि मंच पर बैठे कांग्रेस के नेताओं को ही उनकी बात का कोई सिरा पकड़ नहीं आ रहा था! श्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ के किसान-मज़दूर और ग़रीबों से किए गए वादों से मुकरने वाली प्रदेश सरकार की क़ारस्तानियों को अनदेखा करके राहुल गांधी ने छत्तीसगढ़वासियों को निराश ही किया।

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष श्री साय ने कहा कि पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने बहुत-से लोकलुभावन वादे किए थे, और सत्ता में आने के बाद कांग्रेस की सरकार ने वादाख़िलाफ़ी, झूठ-फ़रेब, छल-कपट करके राजनीतिक पाखंड की सारी हदें ही पार कर दीं। इतना ही नहीं, ख़ुद राहुल गांधी ने छत्तीसगढ़ की किसानों से जगह-जगह फूड प्रोसेसिंग युनिट स्थापित करने और उसमें किसानों के बेटों को रोज़गार देने का वादा किया था, सरकार द्वारा धान ख़रीदी में 15 क्विंटल प्रति एकड़ की लिमिट ख़त्म करने की बात कही थी, अपने उन वादों पर कांग्रेस की प्रदेश सरकार ने अब तक अमल क्यों नहीं किया, यह सवाल पूछने का साहस तक राहुल गांधी नहीं दिखा पाए।

श्री साय ने कहा कि धान ख़रीदने बघेल की डींगों पर राहुल ने यह सच जानने की कोशिश तक नहीं की कि उक्त राशि किसानों को एकमुश्त क्यों नहीं दी जा रही है? जिस ग्रामीण भूमिहीन कृषि मज़दूर न्याय योजना ढिंढोरा पीटा जा रहा है, उस योजनाा में 10 लाख लोगों के बजाय अब वह संख्या 3.35 लाख पर ही क्यों सिमट गई? भाजपा प्रदेश अध्यक्ष श्री साय ने कहा कि भाजपा पर नफ़रत की राजनीति करने का मिथ्या आरोप लगाकर राहुल गांधी कांग्रेस के वैमनस्यपूर्ण, भेदभावपूर्ण, असहिष्णु और अलोकतांत्रिक राजनीतिक चरित्र पर पर्दा डालने के लाख जतन कर लें, लेकिन देश कांग्रेस की असलियत से पूरी तरह वाक़िफ़ है।

श्री साय ने कहा कि भाजपा ने तो शुरू से ही 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास' को अपनी कार्यशैली का मूलमंत्र बनाया है। इसलिए राहुल गांधी अपने नज़रिए को बदलें और देश में नफ़रत और झूठ की राजनीति करके भ्रम फैलाने की ओछी राजनीतिक हरक़तों से बाज़ आएं। श्री साय ने कहा कि देश में धर्म, भाषा, क्षेत्र, जाति के बीच नफ़रत फैलाकर अपने राजनीतिक स्वार्थ साधने वाले कांग्रेस के लोग कांग्रेस के राजनीतिक चरित्र के तराजू पर भाजपा को तौलने की कोशिश न करें। श्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ को पहली बार साम्प्रदायिकता की आग में झोंकने वाली भूपेश-सरकार से बजाय जवाब-तलब करने के राहुल गांधी ने इस पूरे मुद्दे पर मौन साधे रखा! क्या इसे प्रदेश में साम्प्रदायिक विद्वेष और धर्मांतरण के प्रदेश सरकार के छिपे एजेंडे पर कांग्रेस हाईकमान की मौन स्वीकृति माना जाए? भारत की विदेश नीति पर सवाल उठाने वाले राहुल गांधी की राजनीतिक परिपक्वता अगले ही दिन संदेह के घेरे में आ गई जब अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने दो टूक यह कहा कि चीन-पाकिस्तान की नज़दीक़ी वाले राहुल गांधी के बयान से अमेरिका इत्तेफ़ाक़ नहीं रखता। •

डा. रमन सिंह

आम बजट आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में मील का पत्थर साबित होगा

अर्थव्यवस्था को बूस्टर डोज लगाएगा आम बजट

आम बजट 2022-23 मोदी सरकार द्वारा लाया गया एक दूरदर्शी बजट है, जो एक सशक्त, समृद्ध, शक्तिशाली एवं आत्मनिर्भर भारत बनने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। इस जनआकांक्षाओं को पूरा करता यह बजट किसानों की आय दोगुनी करने, मजबूत अवसंरचना, स्वस्थ भारत, सुशासन, युवाओं के लिए अवसर, सभी के लिए शिक्षा, महिला सशक्तिकरण, समावेशी विकास, इत्यादि का संकल्प और मजबूत करेगा।

केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने जो बजट प्रस्तुत किया वह काफी प्रभावशाली है, क्योंकि कोविड जैसी महामारी के बीच यह बजट पेश हुआ है, इस संकट के बाद भी बजट का आकार बढ़ाकर 39.45 लाख करोड़ किया गया है। यह दर्शाता है कि कोरोनाकाल में भी भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है। बजट में किये प्रावधानों से साफ है, यह आम जीवन सरल बनाने के साथ ही, अर्थव्यवस्था को बूस्टर डोज देगा।

इस बजट के चार स्तंभ हैं,पीएम गतिशक्ति, समेकित विकास, उत्पाद संवर्धन एवं निवेश सनराइज अवसर, ऊर्जा संक्रमण और जलवायु कार्य इस तरह बजट को चार भागों में बांटा गया है। बजट में सब वर्गों के साथ ही सभी क्षेत्रों में भी समावेशी विकास को प्रमुखता दी गई है। यह बजट भाजपा सरकार द्वारा सामाजिक न्याय, समानता, सम्मान और समान अवसर की अवधारणा को चरितार्थ करने वाला है।

इस बजट में PMAY योजना हेतु 48000 करोड़ का प्रावधान किया गया है, जिससे गरीबों के 80 लाख आवास बनने हैं लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि छत्तीसगढ़ को इसमें से एक भी आवास नहीं मिलेंगे। क्योंकि भूपेश सरकार ने गरीबों के सर से छत छीनने का काम किया है। हर घर, नल से जल योजना के लिए वर्ष 2022-23 में 60,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। साथ ही राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क में 25000 किलोमीटर का विस्तार दिया जाएगा। तीन साल में 400 उत्कृष्ट वंदे भारत रेलगाड़ियों का निर्माण होगा। इन प्रावधानों से निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ को भी लाभ होगा।

बजट में किसानों का प्रमुखता से ध्यान रखा गया है, जीरो बजट खेती, प्राकृतिक खेती, रिवर लिंकिंग, एक स्टेशन-एक उत्पाद और किसान ड्रोन जैसे विभिन्न प्रयास हमारे किसान भाइयों के लिए किए गये हैं। गेहूं और धान की खरीद के लिए 1.63 करोड़ किसानों को 2.37 लाख करोड़ रुपए का सीधा भुगतान किया जाएगा। 130 लाख एमएसएमई को इमरजेंसी क्रेडिट लिंक्ड गारंटी योजना (ईसीएलजीएस) के तहत अतिरिक्त कर्ज दिया गया है।

इस बजट का महत्वपूर्ण पहलू यह है कि इस बजट में पहली बार पूंजीगत व्यय के लिए 7.5 लाख करोड़ का प्रावधान किया गया है, जो वित्तीय वर्ष 2021-22 में 5.54 लाख करोड़ था, इस प्रकार 2022-23 में पूंजीगत व्यय में 35.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। जो केंद्र सरकार की अधोसंरचना विकास के प्रति दृढ़ता दर्शाता है।

इस बजट के चार स्तंभ हैं,पीएम गतिशक्ति, समेकित विकास, उत्पाद संवर्धन एवं निवेश सनराइज अवसर, ऊर्जा संक्रमण और जलवायु कार्य इस तरह बजट को चार भागों में बांटा गया है।

मैं स्वयं 14 साल प्रदेश का वित्तमंत्री भी रहा हूं, इस लिए यह समझता हूं कि पूंजीगत व्यय में वृद्धि का क्या मतलब होता है। छत्तीसगढ़ में जब भाजपा की सरकार थी तो यह लगभग 17 प्रतिशत था, जो कॉंग्रेस सरकार में घटकर 10 प्रतिशत आ गया है। वित्त मंत्री जी ने कोरोना काल में भी इतनी कुशलता से वित्तीय प्रबंधन किया है कि 2021-22 में अनुमानित राजस्व घाटा जीडीपी का 6.8 प्रतिशत आकलन किया था जो 2022 में राजस्व घाटा 6.9 प्रतिशत आया है। इस तरह वर्ष 2023 -24 के लिए अनुमानित राजस्व घाटा 6.4 प्रतिशत अनुमानित है। जीडीपी दर 9.2 प्रतिशत पूरी दुनिया मे सबसे अधिक है। यह हमारी उपलब्धि है।

भारत को आत्मनिर्भर बनाने के देशवासियों के सपने को साकार करने की दिशा में यह बजट एक बड़ा कदम है। भारत में रक्षा उत्पादन के लिए लागत में दस फीसदी की बढोतरी से हम तेजी के साथ इस क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर होंगे। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में यह बजट भारत के नवनिर्माण में सहयोगी होगा।

भारत के अमृत काल का बजट

- आपदाओं के बीच भी आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था का अवसर, अमृत काल का केन्द्रीय बजट।
- कोरोना के वैश्विक आपदा के बीच भी 39 लाख करोड़ से अधिक का बजट। भीषण आपदा में भी 9.2% की जीडीपी वृद्धि। विश्व में हम नंबर वन।
- सन 2014 के 99 लाख करोड़ से बढ़कर जीडीपी सात वर्षों में 1.50 लाख करोड़।
- केन्द्रीय निधि में राज्यों का हिस्सा 32 से बढ़ाकर सीधे 42/43 प्रतिशत कर दिया। इस वर्ष छत्तीसगढ़ को इससे 8 हज़ार करोड़ अतिरिक्त राशि मिलेंगे।
- अर्थव्यवस्था 2014 के कांग्रेस के शासन में 275 बिलियन डॉलर से बढ़ अब 630 बिलियन डॉलर हुई।
- 2014 तक भारत का निर्यात महज़ 2.50 लाख करोड़ था, पिछले सात वर्षों में यह बढ़कर 4.70 लाख करोड़ हो गया है।
- आज देश में कोई भूखा नहीं है। पर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने मुफ्त अनाज में भी 1500 करोड़ से अधिक का घोटाला किया।
- देश में अब तक 1.10 करोड़ घर बने हैं। केवल इस वर्ष 80 लाख पक्के मकान बनेंगे। इसके लिए इस बजट में 48 हज़ार करोड़ रूपये आवंटित किये गए हैं।
- दुर्भाग्य यह है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के दुराग्रह का खामियाजा गरीबों के सर से छत छिन रहा है।
- इस बजट में रसोई गैस में 4 हज़ार करोड़ की सब्सिडी दी जा रही है। शहरी जनता के लिए भी गृह ऋण में 2.70 लाख की सब्सिडी दिया जा रहा है।
- मनरेगा में 10% मजदूरी वृद्धि की गयी है। इसमें देश के 13.62 करोड़ यानी 10% लोगों को सीधे रोजगार।
- देश में 9 करोड़ घरों तक साफ़ पानी पहुचा। 4 करोड़ पिछले दो वर्ष में। इस बजट में 4 करोड़ और घर जुड़ेंगे। 13 करोड़ घर होंगे लाभान्वित। 40 हज़ार करोड़ से बढ़ कर 60 हज़ार करोड़ आवंटन।
- कृषि को आधुनिकता से जोड़ना। 1.50 लाख करोड़ की रिकॉर्ड अनाज खरीदी। नए सत्र के लिए बजट में एमएसपी के लिए 2.37 लाख करोड़ रूपये का प्रावधान। 68 हज़ार करोड़ रूपये किसान सम्मान निधि के लिए आवंटित।
- खाद सब्सिडी में 33 प्रतिशत वृद्धि करते हुए इसे 80 हज़ार करोड़ से बढ़ा कर 1.50 लाख करोड़ करना। औद्योगिक कोरिडोर की तर्ज़ पर 25 हज़ार किलोमीटर का कृषि कोरिडोर। नदियों को जोड़ने की महत्वाकांक्षी योजना शुरू।
- विश्व में सबसे अधिक 168 करोड़ कोरोना टीके लगे हैं। हमारा टीका दुनिया में श्रेष्ठतम। पहले 70 सालों तक हम लगातार टीकों का आयात करते रहे थे। बीसीजी आदि का टीका यहां दस वर्षों के बाद आता था। अब हम टीकों का निर्यात भी कर रहे हैं।
- हेल्थ बजट में 70 प्रतिशत वृद्धि। कुल 85 हज़ार करोड़। प्राथमिक चिकित्सा के लिए 62 हज़ार करोड़ का प्रावधान।
- विकास और बुनियादी ढांचे, अधोसंरचना के लिए 4 लाख करोड़ से पिछले दो वर्षों में बजट बढ़ा कर 7.50 लाख करोड़ किया गया है। एमएसएमई सेक्टर के लिए 5 लाख करोड़ का आवंटन।
- डिजिटल विश्वविद्यालय जिसमें समूचे देश तक शिक्षा की व्यवस्था। कोरोना के कारण बाधित हुए पढ़ाई को पूरा करने सौ टीवी चैनल समेत शिक्षा में भी अनेक प्रावधान।
- गति शक्ति के माध्यम से सात विभागों का काम एक योजना के तहत लाने की शुरुआत हुई है जिससे सड़क, बिजली, पानी समेत सभी कार्य एक साथ किये जा सकेंगे। भारत के अमृत काल का बजट है।

बजट 2022-23 में छत्तीसगढ़ के लिए ऐतिहासिक इजाफा

छत्तीसगढ़ को पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 8 करोड़ ज्यादा मिलेंगे।

बिलासपुर-दुर्ग के बीच 160 किलोमीटर की रफ्तार से ट्रेन चलाने के लिए रेलवे लाइन के दोनों किनारों पर बैरिकेडिंग करने राशि की स्वीकृति दी गई है।

बजट में एसईसीआर को 17 नई रेल लाइनों की मंजूरी मिली है।

एसईसीआर को बजट में दोहरी लाइन के लिए भी फंड मिला है, इसमें बिलासपुर-उरकुरा 110 किलोमीटर, सलका रोड-खोंगसरा 26 किलोमीटर, चांपा-झारसुगुड़ा 165 कि.मी. तीसरी रेल लाइन, दुर्ग- राजनांदगांव तीसरी रेल लाइन झारसुगुड़ा-बिलासपुर 206 किलोमीटर चौथी लाइन के लिए फंड की व्यवस्था बजट में गई है।

नई लाइन के लिए होगा सर्वे

- तिल्दा-पलारी-बलौदाबाजार-कसडोल-सरसींवा-बरगढ़
- साजा-भाटापारा
- बीजापुर-किरंदुल
- अंबिकापुर से गढ़वा
- भटगांव-प्रतापपुर-वाड्रफनगर
- नारायपुर- दंतेवाड़ा
- बीजापुर-भोपालपट्टनम
- पेंड्रा-अमरकंटक-मंडल

पेड्रा-गेवरा रेललाइन के लिए मिली राशि। रेलवे द्वारा पेंड्रा-गेवरा रोड के बीच 121 किमी की नई रेललाइन निर्माण कराया जा रहा है। बजट में इसके लिए लिए भी अतिरिक्त राशि स्वीकृत की गई। इसके अलावा रायगढ़-भूपदेवपुर, बरवाडीह-चिरमिरी, रायपुर-झारसुगुड़ा, धर्मराजगढ़- कोरबा, चिरमिरी-नागपुर के लिए भी फण्ड की व्यवस्था की गई है।

नई लाइन के लिए राशि

इस बजट में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के लिए 17 नई परियोजनाओं के लिए प्रावधान किया है, इसके लिए बजट में राशि की मंजूरी भी दी गई है।

छत्तीसगढ़ से संबंधित इन 17 परियोजनाओं के लिए राशि स्वीकृत

- कटघोरा-डोंगरगढ़ नई रेल लाइन 294 किमी
- दुर्ग-झारसुगड़ा तीसरी लाइन 350 कि.मी.
- दल्लीराजहरा-जगदलपुर 235 कि.मी.
- वाडसा-गढ़चिरौली 49 किमी
- रायगढ़ माढ़ कोलियारी-भूपदेवपुर 63 किमी.
- पेंड्रारोड-गेवरारोड 121 कि.मी.
- बरवाडीह-चिरमिरी 182 कि.मी.
- रायपुर-झारसुगड़ा 310 कि.मी.
- धरमजयगढ़-कोरबा 63 कि.मी.
- जबलपुर-गोंदिया-बालाघाट कंटगी 285 कि.मी.
- छिदवाड़ा-नागपुर 149 कि.मी.
- छिदवाड़ा-मांडला फोर्ट 182 कि.मी.
- रायपुर-टिटलागढ़ 203 कि.मी.
- मंदिर हसौद - नवापारा रायपुर 20 कि.मी.
- राजनांदगांव-नागपुर 228 कि.मी.
- पेंड्रारोड-अनूपपुर तीसरी लाइन 50 कि.मी.
- अनूपपुर-कटनी 165 कि.मी.
- छत्तीसगढ़ से की गई मांग पर इंटस्ट्रियल कारिडोर को आबंटन
- भारत माला एक्सप्रेस हाईवे रायपुर-विशाखापट्नम के लिए फण्ड का आबंटन
- नागपुर से झारसुगड़ा रेलवे की चौथी लाइन बनाने का आबंटन हुआ है जिसमें छ.ग. प्रदेश भी कवर होगा
- छ.ग. में पोस्ट आफिस की पंजीयन व बिल्डिंग निर्माण हेतु स्वीकृति दी गई है
- बिलासपुर, जगदलपुर अंबिकापुर एयरपोर्ट हेतु भी कार्य को आगे बढ़ाने संबंधित दिशा निर्देश बजट में है
- छत्तीसगढ़ के लाखों किसानों को लगभग 1800 करोड़ से अधिक की राशि किसान सम्मान निधि के रूप में सीधे उनके खाते में भेजी जाएगी •

छत्तीसगढ से संबंधित आंकड़े
सीए अमित चिमनानी के सौजन्य से

बुद्धजीवी सम्मेलन में सिंधिया

मोदी जी की आर्थिक नीति से देश की तस्वीर बदल रही है

एक दिवसीय रायपुर प्रवास पर आये केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एक निजी होटल में आयोजित बुद्धिजीवी सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने कहा कोरोना की भयंकर चुनौतियों के बीच भारत की जीडीपी ने 9.2 प्रतिशत की ग्रोथ दर्ज की है यह विश्व मे सबसे ज्यादा है। जो लोग दो भारत की बात करते है शायद वो उस भारत की बात करते हो जब भ्रष्टाचार चरम पर था ना ना प्रकार के कानून व्यापारियों को परेशान करते थे।

श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा देश के व्यापारियों में खुशहाली तब आएगी जब वे अपना उत्पादन देश के साथ विदेश में भी बेच पाए। मोदी सरकार उसी दिशा में काम कर रही है। 2014 के पहले देश का निर्यात 2 लाख 70 हज़ार करोड़ था आज भारत का निर्यात 4 लाख 50 हज़ार करोड़ हो गया है। उन्होंने कहा कि हर सरकार को सदैव अपने पैरों पर खड़े रहना चाहिये क्योंकि हम सरकार नही सेवक हैं।

जो लोग दो भारत की बात करते है वो 2014 से पहले भ्रष्टाचार वाले भारत और आज भ्रष्टाचार मुक्त भारत की बात करते है बुद्धजीवी सम्मेलन में बोले सिंधिया

श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने चार्टर्ड एकाउंटेंट्स,टैक्स कंसल्टेंट्स ,चैम्बर ऑफ कॉमर्स ,कैट ,उघोग व्यापार संघ व सम्मलेन में बड़ी संख्या में आये व्यापारियों को संबोधित करते हुए कहा है कि आप सभी के सहयोग और सहूलियत के लिए 1085 से ज्यादा कानूनों को वित्त मंत्री ने खत्म कर दिया है। सरकार ने कोरोना से तकलीफ में आये एमएसएमई को कोरोनाकाल में 5 लाख करोड़ रु की मदद अपनी गारंटी देकर की है जिसमें 2 लाख करोड़ का प्रावधान इस बजट में किया गया है। उन्होंने कहा कि अगर मोदी सरकार के नेतृत्व में 2 टीके इज़ाद न होते और सरकार 165 करोड़ डोज टीके जनता को इतने कम समय पर न लगाती तो कोरोना के कारण व्यापार करना बहुत मुश्किल होता।

श्री सिंधिया ने व्यापारियों को संबोधित करते हुए बजट में उनके लिए हुए प्रावधानों को विस्तार से बताते हुए कहा 100 कार्गो टर्मिनल एक तरफ ज्यादा से ज्यादा सामान के डिस्पैच करने में मदद करेंगे और व्यापारियों की लॉजिस्टिक्स कॉस्ट में कमी आएगी। 25 हज़ार किलोमीटर का हाईवे बनने से ट्रान्सपोर्ट कॉस्ट में भी कमी आएगी। अगर व्यापारी की लागत में कमी आएगी तो जनता को उसका सीधा लाभ मिलेगा। अब करदाताओं को 2 साल तक इनकम टैक्स रिटर्न भी रिवाइज करने मौका मिलेगा जिससे वो पेनाल्टी व अन्य कार्यवाहियों से बच सकेंगे। •

समावेशी एवं सर्वांगीण विकास का प्रयास है बजट

बजट 2022-23 भारत को नई दिशा देने वाला एवं विकास की बुलंद बुनियाद देने वाला है। पिछले दो वर्षों से देश वैश्विक महामारी का दंश झेल रहा है। इसके बावजूद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के कुशल नेतृत्व के कारण विकास की गति निर्बाध रूप से आगे बढ़ती रही है। प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत के आह्वान पर देश निरंतर आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर है। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री की दूरदर्शिता से पेश यह बजट गरीबों के उत्थान के लिए, युवाओं की आवश्यकताओं को मजबूती देने के साथ ही देश के विकास को गति देने वाला बजट है। महामारी के खतरे से मुकाबला के बीच यह बजट पेश किया जा रहा है। मोदी सरकार के प्रयासों का ही परिणाम है कि भारत की विकास दर 9.2 प्रतिशत है। इस साल का बजट अगले 25 वर्ष के 'अमृत काल' की नींव रखने और सुदृढ़ अर्थव्यवस्था को दिशा देने का प्रयास है। भारत जब अपनी आजादी के 100 वें वर्ष में प्रवेश करे तो देश के पास एक मजबूत आधार हो। समावेशी विकास, ऊर्जा, प्रोद्योगिकी संचालित पर्यावरण, नवाचार और अनुसंधान एवं विकास के साथ समावेशी बजट का स्तंभ है। देश के हर क्षेत्र से प्रेरणा लेते हुए कुशल तरीक़े से लोगों की जरूरतों को पूरा करनेवाला बजट है। साथ ही इस बजट में बुनियादी ढांचे का विकास, युवा सशक्तिकरण,मध्यम वर्ग को आवश्यक लाभ प्रदान करना, सरकारी विभागों के कार्य को डिजिटल करना, एमएसएमई को मजबूत करने, एक मजबूत वित्तीय परिस्थिति बनाने पर जोर दिया गया है। प्रस्तावित बजट में रोजगार के नये अवसर पैदा करने की पहल की गई है।

डॉ. संजय मयूख

166.68 करोड़ टीकाकरण लक्ष्य हासिल करने के साथ ही मोदी सरकार ने देश के हर एक नागिरक की सुरक्षा और भलाई सुनिश्चित की है। देश के किसानों की आर्थिक ताकत बढ़ाने के लिए भी प्रयास किया गया है। 2022-23 में सरकार का भावी पूंजीगत व्यय 10.68 लाख करोड़ रुपये होने का अनुमान है, जो सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 4.1% है। देश में गरीबों की आवश्यकताओं को देखते हुए एक सम्मानजनक जीवन प्रदान करने के लिए बजट में किफायती आवास योजना के तहत 80 लाख घरों का निर्माण करने का लक्ष्य रखा गया है। युवाओं की जरूरतों को पूरा करने कई अहम फैसले किए गए हैं जो भारत को नई ऊंचाइयअें तक ले जाएंगे। पीएलआई योजनाओं को सफलता मिली है और इसके माध्यम से 60 लाख रोजगार सृजित किये गये है। सरकार ने अनुसंधान पर विशेष जोर दिया गया है। दुनिया ने अनुसंधान व विकास में भारत की ताकत देखी है, जिसने न केवल देश के की जरूरतों को पूरा किया है, बल्कि दुनिया के उन देशों को भी टीके उपलब्ध कराए जो विकास की दौड़ में पीछे रह गए थे। सीमा की सुरक्षा को देखते हुए सैनिकों को सबसे अच्छे उपकरण उपलब्ध कराने के प्रावधान किए गए हैं। सुरक्षित पेयजल के क्षेत्र बड़ी सफलता हासिल की। कुल मिलाकर प्रस्तावित बजट में सभी वर्ग एवं क्षेत्र का ध्यान रखा गया है। •

लेखक बिहार विधान परिषद के सदस्य व भाजपा के राष्ट्रीय सह मीडिया प्रभारी एवं प्रवक्ता हैं।

पूर्व मंत्री से थाने में मारपीट पर आक्रोशित भाजपा

भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता तथा छत्तीसगढ़ शासन के पूर्व कैबिनेट मंत्री राजेश मूणत को गिरफ्तार कर उनके साथ विधानसभा थाने में मारपीट किये जाने पर भड़की भाजपा ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर हमला बोलते हुए कहा है कि यह सत्ता के इशारे पर किया गया सुनियोजित हमला है। सरकार ने सत्ता का खतरनाक दुरुपयोग करते हुए यह बता दिया है कि वह डंडे के जोर पर विपक्ष का दमन कर रही है। पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि पूर्व मंत्री राजेश मूणत सहित भाजपा कार्यकर्ताओं को बिना वजह गिरफ्तार कराकर थाने में मारपीट मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की खीझ का परिणाम है। मुख्यमंत्री बघेल ने लोकतंत्र की मर्यादा तार-तार कर दी। उन्होंने श्री मूणत से व्यक्तिगत खुन्नस निकालने पुलिस का दुरुपयोग किया है।

प्रदेश भाजपाध्यक्ष श्री विष्णुदेव साय ने पूर्व मंत्री श्री राजेश मूणत को पानी पिला कर धरना स्थगित कराया।

प्रदेश भाजपा अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने भाजपा प्रवक्ता श्री मूणत के साथ पुलिस द्वारा की गई मारपीट की तीव्र निंदा करते हुए कहा कि भूपेश बघेल सरकार की गुंडागर्दी का छत्तीसगढ़ की जनता करारा जवाब देगी। भूपेश बघेल अच्छी तरह समझ लें कि जो थोड़ा समय बाकी रह गया है उसमें वे कितना भी दमन करा लें, संघर्ष की कोख से निकला भाजपा का एक-एक कार्यकर्ता उनका मुकाबला करने फौलाद की तरह मजबूत है। वह टूटने वाला नहीं है। नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने कहा कि भूपेश बघेल सरकार छत्तीसगढ़ में जंगल राज चला रही है। पुलिस का दुरुपयोग करके लोकतंत्र के मूल्यों की हत्या की जा रही है। भूपेश बघेल को विरोध बर्दाश्त नहीं होता। वे लोकतंत्र को मवेशी समझकर हांकना चाहते हैं। कानून कायदे की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। डंडे की दम पर विपक्ष का उत्पीड़न किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बघेल सरकार का यह अत्याचार इस सरकार के पतन का कारण बनेगा।

इधर, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता संजय श्रीवास्तव ने प्रदेश के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहु के दिए बयान को दुर्भाग्यपूर्ण बताया. प्रवक्ता श्रीवास्तव ने कहा कि गृह मंत्री के कहे अनुरूप उनकी चुनौती स्वीकार करते हुए भाजपा ने साक्ष्य के रूप में वीडियो जारी किया है। अब अगर नैतिक साहस हो तो गृह मंत्री आरोपी टीआई को बर्खास्त कर दें। उन्होंने कहा कि गृह मंत्री का काम प्रदेश में क़ानून व्यवस्था बहाल करना होता है। उन्हें यह भी सुनिश्चित करना होता है कि शिकायतों पर निष्पक्ष सुनवाई हो और पुलिस किसी तरह का पक्षपात नहीं करे।

भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष व पूर्व विधायक नवीन मार्कण्डेय ने कहा कि भाजपा प्रदेश प्रवक्ता और पूर्व मंत्री राजेश मूणत के साथ थाने में हुई मारपीट को नकार कर प्रदेश सरकार के मंत्री रुद्र कुमार प्रदेश को ग़ुमराह कर रहे हैं। प्रदेशभर में वायरल वीडियो में श्री मूणत के साथ हुई मारपीट के सच को नकारना शर्मनाक है। भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष विकास मरकाम ने कहा कि पूर्व मंत्री श्री मूणत पर लगाए जा रहे आरोप पूरी तरह झूठे और प्रदेश की कांग्रेस सरकार के राजनीतिक प्रतिशोध के एजेंडे से प्रेरित हैं।

पाकिस्तानी आतंकी संगठन को छत्तीसगढ़ में जमीन आबंटन की कोशिश : बृजमोहन

विधायक एवं पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने पाकिस्तानी संगठन दावते इस्लामी को जमीन आवंटन की कोशिश के मामले में खुलासा करते हुए कहा कि ओर जहां छत्तीसगढ़ के हजारों सामाजिक धार्मिक एवं शैक्षणिक संगठन जमीन के लिए ढाई वर्षों से चक्कर लगा रहे हैं, वहीं पाकिस्तान में बने रजिस्टर्ड आतंकी संगठन के नाम पर छत्तीसगढ़ में 25 एकड़ जमीन आवंटन का प्रकरण कांग्रेस सरकार कटघरे में खडी है। कांग्रेस, पाकिस्तानी आतंकी संगठन को जमीन आवंटन के पाप से कभी मुक्त नहीं हो सकती। श्री अग्रवाल ने पाकिस्तानी संगठन दावते इस्लामी के नाम पर राजधानी रायपुर के बोरियाखुर्द में 25 एकड़ जमीन आवंटन व प्रक्रिया को लेकर जब आपत्ति दर्ज कराई गई तो आनन-फानन में शासन एवं प्रशासन ने रात्रि में 1 जनवरी के तारीख में उक्त जमीन के प्राप्त आवेदन को रद्द करने का समाचार जारी करवाया। परंतु वस्तुस्थिति इसके विपरीत है।

श्री अग्रवाल ने कांग्रेस सरकार पर तीखे आरोप लगाते हुए कहा है कि सरकार सत्ता के मद में चूर होकर सिर्फ वोट बैंक के चलते बहुसंख्यक समाज के साथ लगातार अन्याय कर रही है। पाकिस्तानी आतंकी, राष्ट्र विरोधी संस्थाओं को जमीन आबंटन में भी इन्हें कोई दिक्कत नही है। श्री अग्रवाल ने कहा कि पाकिस्तानी संगठनों के लिए जमीन मांगने वाले लोगों व इनके आवंटन की प्रक्रिया में शामिल लोगों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। देश के खिलाफ षड्यंत्र में शामिल लोगों को किसी हालत में बख्शा नहीं जाना चाहिए।

आदिवासी शासकीय सेवकों को पदोन्नति में आरक्षण का लाभ मिले : विकास मरकाम

भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष एवं छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष विकास मरकाम ने 4 फरवरी को अनुसूचित जनजाति शासकीय सेवक विकास संघ तथा सर्व आदिवासी समाज द्वारा प्रदेश के शासकीय कर्मचारियों को पदोन्नति में आरक्षण ना मिलने के कारण आयोजित धरना प्रदर्शन पर भूपेश बघेल सरकार को घेरते हुए कहा है कि शासकीय सेवकों के लिये पदोन्नति में आरक्षण का लाभ आदिवासियों का संवैधानिक अधिकार है। प्रदेश में भूपेश बघेल सरकार के गलत निर्णयों के कारण आदिवासी वर्ग के शासकीय सेवक फरवरी 2019 से पदोन्नति में आरक्षण के लाभ से वंचित हो गये हैं। उन्होंने बताया कि भूपेश बघेल सरकार को सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन करते हुए पदोन्नति का नया नियम बनाना था ताकि पदोन्नति में आरक्षण का लाभ मिल सके परंतु कांग्रेस की ये सरकार इस पर गंभीर नहीं है। भूपेश बघेल सरकार की मंशा वास्तव में पदोन्नति में आरक्षण देने की है तो माननीय सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान निर्णय और जनरैल सिंह निर्णय के अनुसार प्रदेश सरकार को प्रत्येक संवर्ग में अजजा/अजा सदस्यों को अपर्याप्तता के आंकड़े जुटाने चाहिये तथा यह भी दिखाना चाहिये कि पदोन्नति से प्रशासन की कुशलता प्रभावित नहीं होगी, क्योंकि शासकीय कर्मचारी उसी विभाग के हैं।

मानव तस्करी का कलंक कांग्रेस पर : केदार

पूर्व मंत्री व भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता केदार कश्यप ने कहा है कि 05 लाख नौकरियाँ और 45 लाख रोज़गार देने के झूठ का रायता फैला और छत्तीसगढ़ से हो रहे पलायन व मानव तस्करी के कलंक को ढो रही प्रदेश सरकार लाख जतन करके भी सच्चाई छिपा नहीं सकती। पंडरिया ब्लॉक के वनांचल ग्राम अधचरा के 06 बैगा.आदिवासी मज़दूरों को केरल में बंधक बनाकर उनसे काम कराए जाने के सामने आए मामले के परिप्रेक्ष्य में पूर्व मंत्री व भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता केदार कश्यप ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा इन आदिवासी मज़दूरों की सकुशल वापसी के लिए अब तक कोई ठोस पहल नहीं किया जाना प्रदेश सरकार की विफलता और आदिवासी.विरोधी चरित्र का परिचायक है। पूर्व मंत्री व भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता केदार कश्यप ने कहा कि पलायन और उसकी आड़ में मानव तस्करी की वारदातों को छत्तीसगढ़ की नियति बनाने में प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने कोई क़सर बाकी नहीं छोड़ी है।

छत्तीसगढ़ बन गया गांजा कॉरिडोर : सौरभ

बस्तर में एक सड़क हादसे में घायल लोगों की मदद के लिए पहुंची पुलिस को करीब डेढ़ क्विंटल गांजा मिलने पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर कटाक्ष करते नया भाजपा विधायक सौरभ सिंह ने कहा है कि एक पत्ती नहीं बल्कि टनों गांजा छत्तीसगढ़ आ रहा है और मुख्यमंत्री न जाने किस सुरूर में हैं। छत्तीसगढ़ गांजा कॉरिडोर बना दिया गया है। मुख्यमंत्री एक तरफ दिखावे के लिए कहते हैं कि एक पत्ती गांजा भी राज्य में नहीं आना चाहिए। बड़े बड़े दावे किए जाते हैं कि गांजा तस्करी रोकने उपाय किये गए हैं। निगरानी की जा रही है, कैमरे लगाए, ये किया, वो किया लेकिन छत्तीसगढ़ में ऐसा कोई दिन नहीं, जब गांजे की खेप न गुजर रही हो। छत्तीसगढ़ गांजा तस्करों का स्वर्ग बन गया है और बेरोकटोक गांजे का परिवहन ऐसे हो रहा है जैसे अघोषित परमिट जारी कर दिए गए हैं। भाजपा विधयक सौरभ ने कहा कि लगता है कि इन गांजा तस्करों से यूपी चुनाव के लिए फंड इकट्ठा किया जा रहा है।

कांग्रेस सरकार के आर्थिक कुप्रबंधन से छतीसगढ़ बर्बादी की कगार पर: डॉ. रमन

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने कहा है कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार जिस छत्तीसगढ़ मॉडल की बड़ी-बड़ी डींगें हाँककर सियासी लफ्फाजी कर रही है, उसका काला सच आखिरकार सामने आ गया है। डॉ. सिंह ने कर्ज नहीं चुकाने पर नया रायपुर में सरकारी सम्पत्तियों को बैंक द्वारा कब्जे में लिए जाने के मामले में कहा कि इससे साफ है कि कांग्रेस और उसकी प्रदेश सरकार का छत्तीसगढ़ मॉडल गर्त में जा रहा है। भाजपा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. सिंह ने कहा कि प्रदेश को कर्ज के दलदल में आकंठ धंसाने वाली प्रदेश की कांग्रेस सरकार का कार्यकाल किसी कलंक-कथा से कम नहीं है। प्रदेश की भूपेश-सरकार के आर्थिक कुप्रबंधन

और 'ऋणम् कृत्वा, घृतम् पिबेत्' की लत के चलते कल को विधानसभा, चौक-चैराहों के साथ छत्तीसगढ़ महतारी भी गिरवी हो जाएगी। डॉ. सिंह ने कहा कि कर्ज पर कर्ज लेकर इस सरकार ने छत्तीसगढ़ को कंगाली के मुहाने पर ला खड़ा किया है और अब हालत यह है कि कर्ज चुकाने के लिए यह सरकार और ज्यादा कर्ज ले रही है।

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह ने कहा कि हजारों करोड़ों का कर्जा लेकर सरकार उसे उपयोगी तरीके से खर्च नही कर पा रही, वो करोड़ों के नुकसान में चल रहे मेडिकल कॉलेज खरीद रही है,यही कारण है कि कर्ज चुकाने के भी सरकार के पसीने छूट रहे है और सरकारी संपत्ति की नीलामी की स्थिति आ गयी है।

कांग्रेस द्वारा किए आवास घोटाले की राज्यपाल से शिकायत

राज्यपाल सुश्री अनुसुइया उइके से राजभवन जाकर भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि मंडल ने मुलाकात कर बस्तर में हुए प्रधानमंत्री आवास घोटाले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की। इसके साथ ही भाजपा कार्यकर्ताओं पर प्रदेश सरकार के इशारे पर पुलिसिया दुर्व्यवहार पर भी चर्चा हुई। प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने कहा कि प्रदेश में जब से कांग्रेस सत्ता में आई है तब से कांग्रेसियों को भ्रष्टाचार करने, भय फैलाने का लाइसेंस मिल गया है। यह सब कुछ प्रदेश के मुख्यमंत्री के कहने पर हो रहा है। बस्तर में जो आवास घोटाला हुआ है उसकी जांच को लेकर कुछ भी नहीं हो रहा है। हमारे कार्यकर्ता लोकतांत्रिक ढंग से प्रदर्शन कर रहे हैं तो उन पर पुलिसिया कहर बरपाया जा रहा है।

नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने कहा कि अपने हितों के लिए अलोकतांत्रिक प्रक्रिया को अपनाना कांग्रेस का जन्मसिध्द अधिकार बन गया है और इसी रास्ते पर कांग्रेस के कार्यकर्ता चलकर सत्ता के आनंद में मस्त है। उन्होंने कहा कि बस्तर में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के इशारे पर कांग्रेस के दोषी पार्षद को बचाया जा रहा है जिस पर पैसा लेकर आवास देने का आरोप है। पूर्व मंत्री व वरिष्ठ विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि प्रदेश की सरकार दमनकारी नीतियों का सहारा लेकर हमारे कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित कर रही है। बस्तर में जिस तरह से कार्यकर्ताओं पर पुलिसिया कार्यवाही बर्बरता से की गई यह बताता है कि प्रदेश में खौफ की सरकार चल रही है और सारा रिमोट कंट्रोल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के हाथ में है। पूर्व मंत्री व भाजपा प्रदेश प्रवक्ता केदार कश्यप ने कहा कि कांग्रेस की पहली प्राथमिकता भ्रष्टाचार करो, दूसरी प्राथमिकता भ्रष्टचारियों को बचाओं व तीसरी प्राथमिकता पुलिस के मार्फत लोकतांत्रिक प्रक्रिया से प्रदर्शन कर रहे विपक्ष को प्रताड़ित करो। लेकिन इन सबके बाद भी हम भयभीत होने वाले नहीं है और न्याय के खातिर हमारी लड़ाई जारी रहेगी।

राज्यपाल सुश्री अनुसुइया उइके से पीड़ित परिवार के सदस्यों ने मुलाकात कर अपनी पीड़ा से अवगत कराया व दोषी पार्षद सहित इस मामले के जिम्मेदार सभी पर कार्यवाही की मांग की।

कांग्रेस राज में रेत तस्कर छतीसगढ़ की पावन नदियों को बर्बाद कर रहे हैं: भाजपा

नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने कहा कि प्रदेश में रेत तस्करों के नदियों में अवैध उत्खनन के कारण नदी मार्गों में स्थित पुल कमजोर होते जा रहे हैं। रेत तस्करों ने नदी को पूरी तरह खाली कर दिया है जिसके कारण नदियों में बने पुलों के पीलर भी कमजोर हो चुके हैं एवं कभी भी पुल क्षतिग्रस्त हो सकते हैं। श्री कौशिक ने कहा कि अरपा नदी में रेत तस्करों की बुरी नजर लगी हुई है, यहां से रेत तस्कर लगाकार रेत की अवैध तस्करी कर रहे हैं। यह सब प्रशासन के संरक्षण में ही चल रहा है। जिस तरह से रेत माफिया अवैध उत्खनन के चलते नदियों पर बने पुलों के आस पास की जगह को भी नहीं छोड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि राजनांदगांव जिले में भी लगातार रेत की अवैध खनन की शिकायतें ग्रामीण कर रहे हैं। शिवनाथ नदी में जल भराव के बाद भी रेत की अवैध तस्करी का कार्य जारी है। जिसके कारण पूलों के पीलर की स्थिति नाजुक होती जा रही है पुल कभी भी क्षतिग्रस्त हो सकता है।

नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने कहा कांग्रेस के भ्रष्टाचार की नीति ने पवित्र नदियों तक को नही छोड़ा। एक तरफ राज्य सरकार कई जगह पर अरपा पैरी के धार गीत गाती नजर आती है लेकिन उसी मां अरपा को माफियाओं से सरकार बचा नही पाती। श्री कौशिक ने कहा कि प्रदेश सरकार को रेत की अवैध तस्करी करने वाले रेत माफियाओं के खिलाफ तत्काल लगाम कसते हुए कार्यवाही करना चाहिए। प्रशासन उदासीनता कारण रेत माफिया लगातार रेत के अवैध उत्खनन में संलिप्त है जिससे प्रदेश वासियो में भारी रोष व्याप्त है।

लोकसभा ने विशेषाधिकार हनन की नोटिस जारी की

लोकसभा द्वारा छत्तीसगढ़ के पुलिस अधिकारियों को विशेषाधिकार हनन का नोटिस भेजा गया है। सांसद संतोष पाण्डेय लोकसभा के बजट सत्र के दौरान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिडला से मुलाकात कर कवर्धा प्रकरण पर खुद पर लगे 18 धाराओं कि जानकारी देते हुए उचित कार्यवाही किये जाने की मांग की थी। सांसद पाण्डेय ने बताया कि छत्तीसगढ़ की पुलिस सरकार के दबाव में सांसद जैसे संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति की अवमानना कर रही है यह ना सिर्फ व्यक्ति विशेष वरन पद की अवमानना है। इस प्रकार की गलत परम्परा कि शुरुआत कांग्रेस सरकार बदले कि भावना से कर रही है। सांसद ने लोकसभा अध्यक्ष को विस्तृत जानकारी देते हुए बताया था कि पूर्व में उन पर 13 धाराएं लगी थी जिसे पुलिस राज्य सरकार के दबाव में आकार धाराओं को बढ़ाते हुए 18 कर दी है। इसके अलावा वे लगातार राजनांदगांव क्षेत्र का दौरा कर रहे है व लोकसभा की कार्यवाही में शामिल हो रहे है, शासकीय बैठके ले रहे फिर भी नियम कानून को दर-किनार कर पुलिस उन्हें फरार घोषित करते हुए संपत्ति की जानकारी मांग रही है। इस मामले को लेकर छ.ग. के भाजपा सांसदों ने स्पीकर से मिलकर शिकायत की थी।

स्वसहायता समूह की बहनों को मिला अदालती न्याय अहंकारी कांग्रेस के लिए सबक

पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट द्वारा राज्य सरकार के आदेश पर रोक लगाते हुए महिला स्वसहायता समूहों को राहत दिए जाने पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि स्वसहायता समूह की बहनों को मिला अदालती न्याय राज्य की अहंकारी सरकार के लिए सबक है। उन्होंने स्वसहायता समूह की बहनों को जीत की मुबारकबाद देते हुए कहा कि रेडी टू ईट मामले में कोर्ट का फैसला आपके हक की जीत और असंवेदनशील, अराजक भूपेश बघेल सरकार के लिए सबक है। पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने कहा कि मैं आपके साथ हूं। आपके हक के लिए इस अहंकारी कांग्रेस सरकार से आर-पार की लड़ाई साथ लड़ेंगे

और जीतेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने कहा कि कांग्रेस की संवेदनहीन बघेल सरकार ने रेडी टू ईट मध्यान्ह भोजन योजना में लगी 20 हजार बहनों का रोजगार छीनने का पाप किया और राजनीतिक निर्लज्जता दिखाते हुए तीन साल में पांच लाख युवाओं को नौकरी देने का दावा करते हैं। चलाचली के वक्त में भी रोजगार देने की जगह रोजगार छीन रहे हैं। जनता को भ्रमित करने के लिए रोजगार मिशन का झांसा दे रहे हैं। इस सरकार को अदालत के न्याय से सबक लेना चाहिए और न्याय के नाम पर अन्याय की बुरी आदत बदल लेना चाहिए। कांग्रेस की सरकार ने राज्य के हर वर्ग से छल कपट किया है, जिसका दंड भुगतने के लिए वह तैयार रहे।

हिन्दी माध्यम के स्कूल बंद होने से छात्रों का भविष्य अधर में फंसा : कौशिक

नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने कहा कि प्रदेश में हिन्दी माध्यम के स्कूलों को बंद कर दिया जा रहा है जिसके कारण छात्रों का भविष्य अधर में फंस गया है। शिक्षा के विस्तार के लिए नवीन स्कूलों का खोला जाना जरूरी है लेकिन इसको लेकर प्रदेश की कांग्रेस सरकार की कोई तैयारी नहीं दिख रही है। भाजपा सरकार के समय प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए कई सफल प्रयोग किए गए। प्रदेश में भाजपा सरकार के दौरान प्रतिदिन लगभग 7 नवीन शैक्षणिक संस्थानों के विकास, उन्नयन पर कार्य हुए जो ऐतिहासिक है। 2003 में प्रदेश में कुल 21,082 स्कूल संचालित हो रही थी जो भाजपा की सरकार आने के बाद 2018 तक बढ़कर लगभग 60,726 स्कूल हो गए। लेकिन प्रदेश की कांग्रेस जब से सत्ता में आई है स्कूल खोलने के बजाय पुराने स्कूल भवन पर ही आत्मानंद विद्यालय को प्रारंभ किया है जिसे लेकर कोई तैयारी नहीं है। जिसके कारण छात्रों व उनके पालकों के सामने कई संकट खड़े हो गए है। उन्होंने कहा कि पहले से संचालित स्कूल भवनों में आत्मानंद स्कूल खोलकर प्रदेश की कांग्रेस सरकार वाहवाही लूट रही है लेकिन उन स्कूलों में पढ़ने वालों छात्रों के भविष्य की चिंता प्रदेश की सरकार नहीं कर रही है।

नेता प्रतिपक्ष कौशिक ने कहा कि प्रदेश सरकार को आत्मानंद स्कूल के संचालन के लिए नए भवनों का निर्माण करना चाहिए ताकि अध्यापन का कार्य सुचारू रूप से चल सके। हम कहीं भी शैक्षणिक संस्थाओं के उन्नयन व खुलने का विरोध नहीं करते हैं लेकिन प्रदेश सरकार को पूरी तैयारी के साथ आत्मानंद विद्यालय को प्रारंभ करने से पहले व्यवस्था की उचित समीक्षा करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हिन्दी माध्यम के स्कूलों को जिस तरह से बंद किया जा रहा है उसका विरोध करते हैं इन स्कूलों में हिन्दी के साथ अन्य भाषा की पढ़ाई होती है तो बेहतर होगा। जिस तरह से केन्द्र सरकार द्वारा आवासीय एकलव्य व नवोदय विद्यालयों में पढ़ाई हो रही है उस मॉडल में प्रदेश सरकार को आत्मानंद विद्यालय के विस्तार पर कार्य करना चाहिए। जिस तरह की परिस्थितियां आत्मानंद विद्यालय को लेकर प्रदेश में निर्मित हो रही है आने वाले समय में स्थिति विकराल ना हो जाए इसकी चिंता प्रदेश सरकार को छात्रों के उज्ज्वल भविष्य को रखते हुए तत्काल करनी चाहिए।

जनहित के विभिन्न मुद्दों पर कांग्रेस के खिलाफ और अधिकर मुखर होगी भाजपा

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सह-संगठन महामंत्री श्री शिवप्रकाश ने ज़मीनी स्तर पर जनहित के मुद्दों को लेकर पार्टी को मुखर और सक्रिय करने पर बल दिया है। श्री शिवप्रकाश शुक्रवार को राजधानी में कुशाभाऊ ठाकरे स्मृति परिसर स्थित प्रदेश भाजपा कार्यालय में भाजपा व मोर्चा-प्रकोष्ठों के राष्ट्रीय व प्रदेश पदाधिकारियों, कार्यसमिति सदस्यों और ज़िला पदाधिकारियों की बैठक को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह, प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय, प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक व प्रदेश संगठन महामंत्री पवन साय ने भी मार्गदर्शन किया। राष्ट्रीय सह-संगठन महामंत्री श्री शिवप्रकाश ने माइक्रो डोनेशन, मन की बात और सरल पोर्टल विषयों पर मार्गदर्शन किया। पार्टी पदाधिकारियों को टोली बनाकर प्रत्येक बूथ स्तर तक पहुंचना होगा। शक्ति केंद्रों व बूथ स्तर पर पार्टी के संगठनात्मक ढांचे और मज़बूत व सक्रिय बनाने पर चर्चा हुई। इसी तरह विधानसभा स्तर पर जनहित से जुड़े मुद्दों और प्रदेश सरकार की विफलताओं को लेकर आंदोलनात्मक गतिविधि को और तेज़ी देने पर उन्होंने बल दिया। संगठन विस्तार की योजना पर बातचीत की गई ।

किसानों को खाद के नाम पर लूट रही कांग्रेसः संदीप शर्मा

भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के प्रदेश प्रभारी संदीप शर्मा ने कहा कि प्रदेशभर में रबी फसल लेने वाले किसान एक बार फिर खाद के लिए भटकने को विवश हो रहे हैं। एक तरफ सहकारी समितियों में खाद की आपूर्ति नहीं होने से किसानों को खाद का वितरण नहीं हो पा रहा है और खाद के अभाव से किसान हलाकान हो रहे हैं वहीं दूसरी तरफ प्रदेश में खाद की कालाबाज़ारी के चलते किसानों को महंगे दाम पर डीएपी और यूरिया खाद खरीदकर खेती-किसानी का काम करना पड़ रहा है। श्री शर्मा ने कहा कि प्रदेश में खाद का कृत्रिम अभाव

पैदा कर किसानों का शोषण किया जा रहा है। खाद व्यापारी किसानों को खुलेआम लूट रहे हैं और इसे भूपेश सरकार की मौन सहमति मिली हुई है।

भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश प्रभारी श्री शर्मा ने सवाल किया कि जब बाजार में खाद है तो समितियों में क्यों आपूर्ति नहीं की जा रही है? इस प्रकार भूपेश सरकार किसानों की सहकारी समितियों की आय के रास्ते भी बंद करने में आमादा है, दूसरी तरफ निर्धारित समय में धान के उठाव नहीं करने से समितियों में धान का स्टॉक बफर लिमिट से कई गुना अधिक हो गया है, रखरखाव के पर्याप्त संसाधन के अभाव में धान बर्बाद हो रहा है जिससे समितियों को नुक़सान उठाना पड़ रहा है और इसके कारण किसानों की सहकारी समितियों के आर्थिक स्थिति भी बदतर होते जा रही है जिसके ज़िम्मेदार भी भूपेश सरकार ही है।

किसानों पर लाठी बरसाने वाले बघेल खुद को किसान बताना छोड़ दें- भाजपा

भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के रायपुर प्रवास के दौरान नवा रायपुर में किसानों पर लाठियां बरसाये जाने की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल विरोध के स्वर सुनना ही नहीं चाहते। चाहे वह आम जनता का हो, किसान का हो या अपनी ही पार्टी के किसी सदस्य का। राहुल के दौरे के वक्त जो तस्वीर छत्तीसगढ़ की जनता के सामने आई है, वह बता रही है कि किस तरह लोकतंत्र की आवाज को कांग्रेस की सरकार दबा रही है। किसान अपना विरोध प्रदर्शन करने राहुल गांधी के कार्यक्रम स्थल पहुंच गए थे जिन पर पुलिस के द्वारा बेरहमी से लाठियां बरसाई गईं।

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने कहा कि किसानों पर लाठी बरसाने वाले बघेल खुद को किसान बताना छोड़ दें। उन्होंने कहा कि यूपी में किसानों से हमदर्दी और रायपुर में किसानों पर लाठी भूपेश बघेल का दोहरा मापदंड है। भूपेश बघेल यूपी में कांग्रेस की छोटी मैडम की खुशामद में वहां के किसानों के हमदर्द बनकर छत्तीसगढ़ की जनता और किसानों के धन को कांग्रेस का चुनावी फंड समझकर मुआवजावीर बनने की कोशिश करते हैं और अपने ही राज्य के किसानों पर लाठियां भांजने की हरकत करने के बाद उन्हें कोई हक नहीं कि वे खुद को किसान बताते फिरें।

क्या कोई किसान न्याय मांग रहे किसानों पर इस तरह लाठीचार्ज करवा सकता है? भूपेश बघेल किसानों के साथ छलावा करते रहे हैं। उनके साथ राजनीति करते रहे हैं। उन्हें किसानों की पीड़ा से कोई सरोकार नहीं है। उनकी असलियत तो राहुल के दौरे पर किसानों पर चली निर्मम लाठियों से उजागर हो चुकी है। अब किसानों को भूपेश बघेल को अपनी किसान बिरादरी से बहिष्कृत कर देना चाहिए। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने कहा कि किसानों से छल कपट करके सत्ता में आई कांग्रेस पहले दिन से ही किसानों के शोषण में लगी हुई है। 2500 का झुनझुना पकड़ाकर उनकी सारी सब्सिडी बंद कर दी गई। कर्ज माफी के नाम पर दिखावा किया गया। किसान की हालत खराब है वे आत्महत्या कर रहे हैं, सरकार हर साल उनकी धान खरीदी में हीलाहवाली करती है। तमाम प्रपंच रचे जाते हैं। धान खरीदी से बचने बारदाने की राजनीति की जाती है। किसान से ज्यादा धान लेकर उसे लूटा जा रहा है। देर से धान खरीदी शुरू करने के कारण किसानों का भारी नुकसान हुआ, उन्हें पर्याप्त मुआवजे की दरकार से सरकार को कोई हमदर्दी नहीं है। दिल्ली सीमा पर किसान को समर्थन देने का नाटक करने वाले राहुल गांधी से अगर रायपुर के किसान मिल लेते तो भूपेश बघेल को इसमें क्या गलत लगा? उन्होंने कहा कि बघेल अपनी आंखों से राहुल को छत्तीसगढ़ दिखाना चाहते थे इसलिए वे अपनी ढोल की पोल खुलने के डर से किसानों को बर्दाश्त नहीं कर पाए।

कांग्रेस की कब्जा संस्कृति ने कबीरपंथ के संत को भी नहीं बख्शाः भाजपा

छत्तीसगढ़ प्रदेश भाजपा अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने राजधानी के सिविल लाइन थाना क्षेत्र के कटोरा तालाब स्थित कबीरपंथ के संतश्री प्रकाशमुनि नाम साहेब के मकान और आश्रम के ऊपर कांग्रेस के एक नेता द्वारा कब्जा करने की खबर पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा है कि कांग्रेस की गुंडागर्दी की हद हो गई। संतों तक को नहीं बख्शा जा रहा। कबीरपंथ के गुरु के घर और आश्रम पर कांग्रेसी नेता के अवैध कब्जे और अभद्रता के बाद भी पुलिस का यह कहना कि मामला शांत हो गया है, साबित कर रहा है कि प्रदेश में कानून का नहीं बल्कि कांग्रेसियों का गुंडाराज चल रहा है। कानून के राज की दुहाई देने वाले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कांग्रेसी गुंडों, अवैध कब्जों, माफियाओं के प्रधान संरक्षक बन गए जान पड़ रहे हैं। सरकार के संरक्षण में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की अवैध खनन, अवैध कब्जा संस्कृति फलफूल रही है। पुलिस के हाथ बंधे हुए हैं। धर्म गुरु भी कांग्रेसी गुंडागर्दी के शिकार हो रहे हैं। उन्होंने पूछा कि क्या भूपेश बघेल का सर्व धर्म समभाव और गांधी दर्शन यही है कि धड़ल्ले से अवैध कब्जा करने की छूट कांग्रेस के लोगों को दे रखी है।

प्रदेश भाजपा अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने कहा कि संतश्री प्रकाशमुनि नाम साहेब के आश्रम के ऊपर अवैध कब्जा करने वाले कांग्रेस नेता पर तत्काल कार्रवाई की जानी चाहिए और गांधीवाद के नाम पर ढकोसला करने वाली कांग्रेस को अपने उस नेता को फौरन कांग्रेस से बाहर करना चाहिए। वरना यह माना जायेगा कि कांग्रेस को गांधी दर्शन से दूर दूर तक कोई सरोकार नहीं है, वह सिर्फ अराजक ताकतों का खिलौना बनकर रह गई है। पिछले तीन साल से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के राज में चोर, लुटेरे, गुंडे, बदमाश, तस्कर, माफिया का राज चल रहा है।

हमारा बूथ हो सबसे मजबूत : नितिन नबीन

भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश सह प्रभारी अपने एक दिवसीय दौरे पर प्रदेश के बलरामपुर जिले पहुंचे। अपने एकदिवसीय प्रवास पर पहुंचे प्रदेश सह प्रभारी नितिन नबीन ने पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि जिला के सभी मंडलों का संगठनात्मक गठन एवं रचनात्मक कार्यों पर भाजपा के हर कार्यकर्ता अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। उन्होंने सभी मंडल अध्यक्ष का हौसला बढ़ाते हुए कहा कि हमें बूथ स्तर पर जाकर कार्य करना होगा तथा बूथ के कार्यकर्ता अपने-अपने बूथों को मजबूत करने की दिशा में अभी से जूट जाए। प्रदेश की कांग्रेस सरकार को भ्रष्ट सरकार बताते हुए कहा कि जब से प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी है तब से प्रदेश में आए दिन भ्रष्टाचार, लूट, हत्या, अपहरण, दुराचार, छेड़छाड़ की घटना घटित हो रही है। राज्यसभा सांसद रामविचार नेताम ने कहा कि मिशन 2023 के लिए प्रत्येक कार्यकर्ता को अभी से जुड़ना होगा। विधायक एवं प्रदेश महामंत्री नारायण चंदेल ने कार्यकर्ताओं को संगठित होने के लिए कहते हुए कहा कि भाजपा का प्रत्येक कार्यकर्ता एक कर्मयोगी कार्यकर्ता है, और मिशन 2023 में विजय हासिल करने के लिए अभी से तैयार होना होगा। पूर्व गृह मंत्री राम सेवक पैकरा ने कहा कि हमें अभी से मिशन 2023 की तैयारी करना है। प्रदेश सरकार की विफलताओं को हमें जन-जन तक पहुंचाना है। अनुसूचित जनजाति आयोग के पूर्व राष्ट्रीय नंदकुमार साय ने 2023 में भाजपा की सरकार बनाने का संकल्प दिलाया। जिलाध्यक्ष गोपाल प्रसाद मिश्रा ने स्वागत उदबोधन किया। बैठक को अन्य पदाधिकारियों ने भी संबोधित किया। राज्यसभा सांसद रामविचार नेताम ने प्रदेश सह प्रभारी नितिन नबीन को श्रीफल एव साल तथा प्रतीक चिन्ह देकर उनका स्वागत किया। बैठक का संचालन ओमप्रकाश जायसवाल ने तथा आभार जिला महामंत्री जयप्रकाश गुप्ता ने किया। इस दौरान बैठक में ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष अखिलेश सोनी, मेजर अनिल सिंह, नरेश नंदे, सिध्दनाथ पैकरा, सहित जिला के पदाधिकारी, मंडल अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभी मोर्चों के अध्यक्ष उपाध्यक्ष सहित बड़ी संख्या में पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद रहे।

खाद किसानों के पास नही तो मुनाफाखोरों के पास कैसी पहुँची?

भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के प्रदेश प्रभारी संदीप शर्मा ने कहा है कि प्रदेशभर में व्याप्त खाद संकट 'भूपेश निर्मित' है और इसके चलते कांग्रेस आलाकमान के लिए एटीएम मशीन के तौर पर काम कर रही प्रदेश सरकार के संरक्षण में प्रदेशभर में जमाखोरों, मुनाफ़ाखोरों और कालाबाज़ारियों ने रबी फ़सल के लिए खाद का मनमाना भंडारण और खाद की आपूर्ति ठप कर किसानों को हलाकान कर रखा है। श्री शर्मा ने कहा कि अपने घोर किसान-विरोधी चरित्र के चलते पूरी तरह बेनक़ाब हो चुकी प्रदेश की भूपेश-सरकार अपनी नाकामी छिपाने केंद्र सरकार पर कोई-न-कोई अनर्गल आरोप जड़ देने और मिथ्या प्रलाप करने की आदत से लाचार है।

भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश प्रभारी श्री शर्मा ने कहा है कि प्रदेशभर में रबी फसल लेने वाले किसान एक तरफ़ रासायनिक खाद के लिए भटकने को विवश हो रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ़ प्रदेश में रासायनिक खाद का कृत्रिम संकट पैदा करके जमाखोर-कालाबाज़ारी जमकर नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं। सहकारी समितियों में खाद की आपूर्ति नहीं होने से किसानों को खाद का वितरण नहीं हो पा रहा है और खाद के अभाव से किसान हलाकान हो रहे हैं वहीं प्रदेश में खाद की कालाबाज़ारी के चलते किसानों को खाद नहीं दी जा रही है और उनको महंगे दाम पर डीएपी और यूरिया खाद खरीदकर खेती-किसानी का काम करना पड़ रहा है। श्री शर्मा ने कहा कि प्रदेशभर के खाद बिक्री केंद्रों में सामने आईं गड़बड़ियाँ और तीन केंद्रों का लाइसेंस निलंबित किए जाने की कार्रवाई से यह आईने की तरह साफ़ हो गया है कि प्रदेश में खाद का कृत्रिम अभाव पैदा कर किसानों का शोषण किया जा रहा है। खाद व्यापारी किसानों को खुलेआम लूट रहे हैं और इसे भूपेश सरकार की मौन सहमति मिली हुई है। श्री शर्मा ने कहा कि जब बाजार में खाद है तो आपूर्ति नहीं किया जाना व्यापारियों से मिलीभगत का साफ़ संकेत है। कांग्रेस, कमीशन और करप्शन, कालाबाजारी सबका गोत्र एक ही है जिसे छत्तीसगढ़ के किसान भुगत रहे हैं।

छिना ज़ीरो पावर कट का तमगा, प्रदेश में विकास की जगह विनाश हो रहा

सूभारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने कहा है कि प्रदेश की पूर्ववर्ती भाजपा सरकार के शासनकाल में जिस छत्तीसगढ़ को बिजली उत्पादन और आपूर्ति के मद्देनज़र ज़ीरो पॉवर कट स्टेट का गौरव हासिल हुआ था, उस छत्तीसगढ़ को हर मोर्चे पर नाकारा साबित हो चुकी प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने बिजली कटौती वाले देश के पाँच राज्यों में शुमार कर देने का शर्मनाक कृत्य किया है। श्री साय ने प्रदेश के ज़ीरो पॉवर कट का तमगा छिन जाने के लिए अपने निकम्मेपन पर बजाय शर्म महसूस करने के प्रदेश सरकार के प्रवक्ता और मंत्री रवीन्द्र चौबे इसे राजनीति-प्रेरित बताकर प्रदेश सरकार के मानसिक दीवालिएपन का परिचय दे रहे हैं।

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष श्री साय ने कहा कि चालू वित्तीय वर्ष में अक्टूबर तक छत्तीसगढ़ के ग्रामीण क्षेत्रों में 539.40 घंटे और शहरी क्षेत्रों में 50.45 घंटे की औसत कटौती की जानकारी राज्यसभा में केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह ने दी है। तथ्य और सत्य को झुठलाकर अपनी विफलताओं का ठीकरा दूसरों के मत्थे फोड़ना राजनीतिक कुंठा की शिकार कांग्रेस सरकार की नियति हो चली है। श्री साय ने कहा कि प्रदेश सरकार को अपने झूठ का रायता फैलाते समय इस बात का होश ही नहीं रहता कि प्रदेश में सभी श्रेणी के बिजली उपभोक्ताओं की संख्या में भारी इज़ाफ़े के बावजूद कोई नया सरकारी बिजली संयंत्र नहीं लगने की बात बिजली विभाग के अधिकारी कह रहे हैं। पिछले साल 240 मेगावाट का संयंत्र भी बंद हो गया है तथा अभी एक और संयंत्र को बंद करने की तैयारी चल रही है! श्री साय ने कहा कि मांग के अनुरूप बिजली उत्पादन क्षमता बढ़ाने के बजाय प्रदेशभर को बिजली की घोषित-अघोषित कटौती के ज़रिए अंधकार युग में धकेलने वाली प्रदेश सरकार अब बिजली को लेकर अनर्गल बयानबाजी कर रही है।

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष श्री साय ने कहा कि जब से प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आई है, हमसे सिर्फ़ हर चीजें छिनती जा रही हैं और छत्तीसगढ़ रिवर्स गियर पर है। नया तो छत्तीसगढ़ को कुछ मिल नहीं रहा है, उल्टे जो कुछ हासिल था, वह भी कांग्रेस की यह प्रदेश सरकार बर्बाद करने और लुटाने में ही लगी है। श्री साय ने कहा कि ज़ीरो पॉवर कट स्टेट का तमगा छिन गया है, किसानों को बिजली नहीं मिलने से खेती-किसानी का काम प्रभावित हो रहा है, लोगों के ज़रूरी काम प्रभावित हो रहे हैं। जब तक प्रदेश में कांग्रेस सरकार सत्ता में रहेगी, बर्बादी के अलावा छत्तीसगढ़ को कुछ हासिल नहीं होने वाला है। श्री साय ने कहा कि केंद्र सरकार के ख़िलाफ़ रूदाली-रूदन करने और मंत्रियों से झूठ कहलवाकर प्रदेश सरकार अपने शर्मनाक कृत्यों पर पर्दा नहीं डाल सकेगी। प्रदेश सरकार केंद्र से अवार्ड मिलने पर तो यह कहकर कि, भाजपा की सरकार हमें हमारे अच्छे काम के लिए अवार्ड दे रही है, फूलकर कुप्पा हुई जाती है तो अब ज़ीरो पॉवर कट स्टेट का तमगा छिन जाना उसे राजनीति-प्रेरित और ख़राब क्यों लग रहा है?

छत्तीसगढ़ को अपराध गढ़ बना दिया है कांग्रेस ने : कौशिक

नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने कहा कि जिस तरह से प्रदेश में अपराध का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है इस पर अंकुश लगाने के लिए प्रदेश सरकार कुछ ऐसा नहीं कर रही है जिससे आम लोगों मन में अपराध के प्रति भय खत्म हो जाए। उन्होंने कहा कि एक वैवाहिक समारोह में सरेआम एक युवक की हत्या कर दी जाती है उसके बाद भी प्रदेश की कांग्रेस सरकार और उनके पुलिस केवल कार्यवाही के नाम पर बयानबाजी में करने में ही जुटी रहती है। जिस तरह से प्रदेश में 8 फरवरी को आजाद नगर थाने इलाके में एक युवक पर चाकू से हमला कर घायल कर दिया जाता है तो वहीं 11 फरवरी को खमतराई इलाके में चाकूबाजी के मामलें में लहु लुहान हालात में एक युवक मौके पर बेहोश स्थिति में मिलता है। 12 फरवरी को रायपुर के पंडरी इलाके में 5 युवक पटाखे फोड़ने के मामूली विवाह पर हमला कर देते है। 12 फरवरी को गुढ़ियारी इलाके में पुरानी रंजिश के चलते बदमाशों द्वारा एक युवक को चाकू मार कर घायल कर दिया जाता है। इससे स्पष्ट है कि पुलिस को लेकर अपराधियों में कोई खौफ नहीं है। जिसके कारण ही राजधानी रायपुर सहित पूरा प्रदेश क्राइम कैपिटल में बदलता जा रहा है। नेता प्रतिपक्ष कौशिक ने कहा कि जिस तरह के हालात अपराध को लेकर प्रदेश में बनती जा रही है इससे शांति के द्वीप का प्रदेश छत्तीसगढ़ की छवि लगातार बिगड़ती जा रही है जिसके लिए प्रदेश की कांग्रेस सरकार और उनकी नीति जिम्मेदार हैं। पूरे देश में अपराध को लेकर छत्तीसगढ़ कई मामलों में अव्वल है जो बेहद ही चिंताजनक है। पुलिस कर्मियों के हत्या के मामलें में पहले स्थान पर है। किशोरों द्वारा किए गए अपराध के मामलें में पहले स्थान पर। अनुसूचित जनजाति के नाबालिग बच्चों के दुष्कर्म के मामले में दूसरे स्थान पर, बच्चों के विरूध्द घटित अपराध के मामलें में तीसरे स्थान पर व हत्या के मामलें में पूरे देश में तीसरे स्थान, बलात्कार के मामलें में 6वें स्थान पर, अपहरण के मामलें में 7वें स्थान पर व महिलाओं में विरूध्द घटित अपराध के मामलें में 12वें स्थान पर हैं। •

भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में भारतरत्न पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी की 97वीं जयंती के अवसर पर 'दीप कमल' पत्रिका के अटल स्मृति विशेषांक का विमोचन किया गया। इस मौके पर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह, कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रदेशाध्यक्ष विष्णदेव साय व विशिष्ट अतिथि नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक, पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल, सांसद सुनील सोनी, संतोष पाण्डे व प्रदेश संगठन महामंत्री पवन साय मौजूद थे। कार्यक्रम के मुख्यवक्ता, पार्टी पत्रिकाएं व प्रकाशन विभाग के राष्ट्रीय प्रमुख डॉ. शिव शक्ति बक्सी थे।

अटल, अडिग, अद्वितीय, अद्भुत और सदा आधारस्तम्भ रहेंगे

अटलजी ने दिया हमारे सपनों का छत्तीसगढ़

इस मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने कहा कि भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की विनम्रता ही जीवन के वैचारिक विशालता के साथ हम सब को जोड़े रखा है। सरल, सहज व सर्वमान्य उनके व्यक्तित्व ने हम सबको राजनीतिक जीवन में प्रशिक्षित किया है। उन्होंने हमारे सपनों के छत्तीसगढ़ को गढ़ा है और छत्तीसगढ़ के समग्र विकास के लिए उनकी परिकल्पना हमें सदैव प्रेरित करती रहेगी। डॉ. रमन ने कहा कि प्रदेश में जब से कांग्रेस की सरकार सत्ता में आई है, अटल जी के उद्देश्यों पर अंकुश लगाया है और राज्य का विकास भी थम गया है। इस सरकार को करारा जवाब देकर हमें अटल जी के सपनों का छत्तीसगढ़ बनाना होगा।

दीपकमल का संग्रहणीय अंक

भाजपा प्रदेशाध्यक्ष विष्णुदेव साय ने कहा कि अटल जी के जीवन के संपूर्ण संदर्भों को किसी किताब में लाना कठिन है लेकिन दीपकमल की टीम ने उनकी सहजता को साहित्य के रूप में प्रस्तुत किया है। निश्चित ही यह अंक सबके लिए संग्रहणीय होगा। उन्होंने अपने संसदीय कार्यकाल को याद करते हुए कहा कि मुझे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी के साथ कार्य करने

का अवसर मिला और हम सबने उनसे सामाजिक जीवन की संस्कार लिये हैं सदन में उन्हें सुनना सुखद अनुभव होता था और यह पल हम कभी छोड़ना नहीं चाहते थे।

अविस्मरणीय अटल योगदान

नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने कहा कि अटल जी का छत्तीसगढ़ से नाता उसके निर्माण से लेकर समग्र विकास का रहा है। वे सदैव छत्तीसगढ़ की भावनाओं को एक राज्य का स्वरूप देना चाहते थे इसलिए राज्य निर्माण में उनके योगदान को नहीं भुलाया जा सकता।

त्याग, तपस्या और शुचिता के प्रतीक

विधायक व पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि त्याग तपस्या और शुचिता के सिद्धांत को अटल जी ने सार्वजनिक जीवन में स्थापित किया है। हम सबके अग्रपंथी अटल जी परिस्थितियों के सामने कभी समझौता नहीं किया।

अटलजी के कृतित्व पर आधारित प्रदर्शनी का अवलोकन।

छत्तीसगढ़ से आत्मीय लगाव

सांसद सुनील सोनी ने कहा कि अटल जी ने हमें विषम परिस्थितियों में कार्य के लिए तैयार किया है। उनका छत्तीसगढ़ से आत्मीय लगाव ऐसे कई अवसरों का साक्षी बने हैं। सांसद संतोष पाण्डे ने कहा कि विश्व की संसदीय इतिहास में अटल बिहारी वाजपेयी जी के संसदीय कार्यकाल के बराबर शायद ही किसी का होगा। उन्होंने हम सबको बाधाओं को लांघने की कला सिखाई है।

अटलजी के हाथों लोकार्पण का सौभाग्य

दीप कमल के संपादक सुभाष राव ने कहा कि पत्रिका के प्रकाशन का 19वां वर्ष है और हमने जब इसकी शुरूआत की थी तब इसका लोकार्पण पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया था। अब एक सुखद अवसर है कि उनके जीवन कृतित्व पर केन्द्रित अंक का विमोचन कर रहे हैं। भाजपा प्रकाशन विभाग प्रमुख एवं दीप कमल के कार्यकारी संपादक पंकज झा ने कहा कि करोना काल में परिस्थितियां निर्मित हुई थी उसके बाद से अब दीप कमल को नये कलेवर के साथ प्रकाशित करने जा रहे हैं निश्चित ही यह अंक सबको हमेशा की तरह पसंद आयेगा। कार्यक्रम में आभार प्रदेश मंत्री ओ.पी. चैधरी ने किया। •

राष्ट्रपति के आदिवासी दत्तक पुत्रों के अस्तित्व पर सवाल?

पंकज झा

ख़ूबसूरत पहाड़ियों से घिरा छत्तीसगढ़ का पर्यटन स्थल है सतरेंगा। खनिज संपन्न देश के ऊर्जा का एक बड़ा केंद्र कोरबा जिले में अवस्थित इस स्थल की सबसे बड़ी पहचान कोरवा जनजाति हैं। कोरवा और सरगुजा में निवासरत पंडो आदि जनजाति को राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र के रूप में मन्यता प्राप्त है। इन्हें संविधान के द्वारा भी अनेक संरक्षण मिले हैं। उसी सतरेंगा के निवासी पहाड़ी कोरवा सुखसिंह की पत्नी सोनी बाई कोहनी में मामूली फ्रैक्चर के इलाज के लिए कोरबा के ज़िला अस्पताल में अपने बेटे के साथ पहुंची थी। वहां एक बिचौलिए ने उन्हें एक निजी अस्पताल भेज दिया जहां ऑपरेशन से पहले ही उक्त महिला की मौत हो गई। कोहनी के मामूली-से फ्रैक्चर के इलाज के दौरान ही पहाड़ी कोरवा महिला को जान से हाथ धोना पड़ गया। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य एवं क़ानून व्यवस्था में खामी का ऐसा कोई अनोखा मामला नहीं है। भाजपा सांसद रामविचार नेताम के सवालों के जवाब में केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने जानकारी दी कि छत्तीसगढ़ में 955 महिलाओं ने तो केवल प्रसव के दौरान दम तोड़ दिया है।

इसके अलावा उच्च सदन में दी गयी जानकारी के अनुसार पिछले तीन वर्ष में छत्तीसगढ़ में 25 हज़ार 164 आदिवासी बच्चों की जानें गयी हैं। इन बच्चों में 13 हज़ार से अधिक नवजात शिशु और 38 सौ से अधिक छोटे बच्चे-बच्चियां थे। दुर्भाग्य की बात यह है कि अधिकांश की मौत निमोनिया, खसरा, डायरिया जैसे आजकल मामूली समझी जाने वाली बीमारियों के कारण हुई है। भाजपा प्रवक्ता एवं पूर्व मंत्री केदार कश्यप कहते हैं – 'प्रदेश की कांग्रेस सरकार के नकारेपन और बदहाल हो चली स्वास्थ्य सेवाओं का इससे बड़ा प्रमाण और क्या हो सकता है! प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव भी स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर ख़ूब बड़ी-बड़ी डींगें हांकते रहते हैं, जबकि ज़मीनी हक़ीक़त यह है कि प्रदेश सरकार की बदनीयती, कुनीतियों और नेतृत्वहीनता के चलते प्रदेश के लोग बेहतर इलाज के लिए दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं और इलाज के बदले उन्हें मौत मिल रही है।' प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री टी. एस. सिंहदेव ने इन आंकड़ों पर टिप्पणी से इनकार किया है।

सरगुजा संभाग में विशेष संरक्षित पंडो जनजाति के 50 से अधिक लोगों की रहस्यमय मौत इससे पहले भी हुई। वजह भूख और कुपोषण बताया गया। प्रदेश में बच्चों व महिलाओं की मौत ने सरकार के ऐसे कथित सुपोषण अभियान को आईना दिखाया है। बकौल प्रदेश में नेता प्रतिपक्ष मुख्यमंत्री धरमलाल कौशिक – 'प्रदेश में कथित सुपोषण अभियान भी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई है। कुपोषण में मार्च 2021 जुलाई 2021 तक 4 प्रतिशत की वृध्दि हुई है तथा प्रदेश पोषण के मामले में 30वें स्थान पर है जो शर्मनाक है। प्रदेश में 61 प्रतिशत महिलाएं एनीमिक है।' प्रदेश में विधानसभा में इस बात को स्वीकारा गया है कि मार्च 2020 में कुपोषण की दर 18.22 प्रतिशत थी तो वहीं मार्च 2021 में 15.15 प्रतिशत हो गई थी। कुपोषण की दर जुलाई 2021 में 19.86 प्रतिशत हो गई अर्थात जुलाई 2021 की स्थिति से कुपोषण की दर में 4 प्रतिशत की वृध्दि हो गई है।

केन्द्र सरकार द्वारा करीब 1500 करोड़ रुपए कुपोषण के खिलाफ जारी लड़ाई के लिए दिए गए तो वहीं लगभग 400 करोड़ रुपए सुपोषण अभियान के लिए डीएमएफ व सीएसआर मद से उपलब्ध कराई गई। प्रदेश में लगभग 3000 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद भी कुपोषण के खिलाफ जारी लड़ाई में प्रदेश की सरकार नाकाम रही है। इससे अधिक शर्मनाक बात क्या हो सकती है कि जो प्रदेश धान का कटोरा कहा जाता हो, वहां के माटी पुत्र-पुत्रियों की कुपोषण से मौत हो जबकि दावे यहां सुपोषण के बड़े-बड़े किये जा रहे हैं। हालत यह है कि इन संरक्षित जनजातियों के हित में काम करने के बजाय प्रदेश के एक कैबिनेट मंत्री ने संरक्षित जनजाति की ज़मीन हड़प ली थी, विपक्ष द्वारा इस मामले को उठाने और मीडिया में आ जाने के कारण अंततः आदिवासी परिवार की ज़मीन वापस मिली।

जहां तक स्वास्थ्य व्यवस्था का सवाल है तो छत्तीसगढ़ के बस्तर से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत की थी। उससे पहले भी प्रदेश में भाजपा की सरकार के समय स्मार्ट कार्ड योजना से भी हर व्यक्ति को 50 हज़ार रूपये तक का इलाज मुफ्त होता था। लेकिन सत्ता में आते ही कांग्रेस ने उन सभी योजनाओं को ख़त्म करते हुए खुद की योजना लाने की कोशिश की। स्वास्थ्य मंत्री टी. एस. सिंहदेव ने कार्यभार सम्हालते ही थाईलैंड जाकर वहां की चिकित्सा व्यवस्था का अध्ययन किया। लेकिन ढाक के तीन पात ही साबित हुए सभी। न तो नयी कोई व्यवस्था आ पायी और न ही पुरानी व्यवस्था ही संचालित हो पायी। ढाई-ढाई साल के फार्मूले पर मुख्यमंत्री बने भूपेश बघेल को सत्ता स्वास्थ्य मंत्री को ट्रांसफर करना था, इसके लिए होते रहे खींचतान के कारण हमेशा स्वास्थ्य विभाग को खामियाजा भुगतना पडा। हालत इतने खराब हो गए थे कि स्वास्थ्य विभाग की बैठक में ही स्वास्थ्य मंत्री को नहीं बुलाया जाता था। कोरोना की विभीषिका के बीच मंत्री सिंहदेव मुंबई में जा कर बैठ गए थे।

अविभाजित मध्यप्रदेश के ज़माने से ही प्रदेश के आदिवासी सबसे उपेक्षित और शोषित रहे। तमाम प्राकृतिक एवं वन्य संपदा के बावजूद यहां के आदिवासी आंत्र शोध जैसी बीमारियों का शिकार होकर मरते रहे थे। वे अपनी कीमती वन्य संपदा, चिरौंजी जैसी फसल नाकाम के भाव बेचते रहे थे। कांग्रेस के ज़माने में उनके साथ हुए अन्यायों की गाथा अंतहीन है। प्रदेश बनने के बाद इनके दिन बहुरने की आस बंधी। डा. रमन सिंह की सरकार ने इनके लिए चिकित्सा, भोजन और शिक्षा समेत सभी क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किये थे। उन तक लगभाग मुफ्त चावल, नमक आदि पहुचाने की योजना ने तो विश्व स्तर पर चर्चित हुई थी। लेकिन हाल के वर्षों में हालत फिर से भयावह हो गए हैं। बड़ी मुश्किल से प्रदेश ने मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर को कम करने में सफलता हासिल हुई थी। मातृ मृत्यु दर वर्ष 2003 में प्रति एक लाख पर 365 थी, जो 2018 तक घट कर 173 हो गई। इस अवधि में शिशु मृत्यु दर प्रति एक हजार पर 70 से घट कर 39 रह गई थी। राज्य में बच्चों के सम्पूर्ण टीकाकरण का प्रतिशत 48 से बढ़कर 76 और संस्थागत प्रसव का प्रतिशत 18 से बढ़कर 70 हो गया था। लेकिन पिछले तीन साल में बच्चों के मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ते जाना चिंताजनक है। अभी राज्यसभा में दिए भयावह आंकडें से उम्मीद है कांग्रेस सरकार की नींद खुले। हालांकि इसकी उम्मीद कम ही है कि स्वास्थ्य मंत्री और मुख्यमंत्री के बीच छिड़ी जंग को इन हज़ारों नौनिहालों की मौतें भी लगाम लगा पाये। •

रायपुर में केंद्रीय बजट पर संगोष्ठी के वक्ता केंद्रीय कैबिनेट मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया।

रायपुर प्रवास के दौरान भाजपा पदाधिकारियों से नागर विमानन मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का संवाद।

राजमाता को श्रद्धा-सुमन अर्पित करते पौत्र श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया।

भाजपा की प्रांतीय बैठक में राष्ट्रीय सहसंगठन महामंत्री श्री शिवप्रकाश जी का मार्गदर्शन।

...आएंगे फिर योगी ही